Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:45 PM Page 1

हमारे डिजीटल प्लेटफार्म
www.scgnews.in
scgnews Social Channel Group
YouTube

RNI NO. CHHHIN/2023/87466

लाईफ वर्सिटी

मासिक

शिकायतों से ज्यादा शुक्रियाँ कहिये. जिंदगी आसान हो जायेगी

वर्ष : 2 | अंक : 04 | माह : सितम्बर 2024 | पृष्ठ : 8 | संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, 8817194979 | मूल्य : 5 रू.

क्या मोदी विदेश नीति में वो चमक नहीं रही ?

नरेन्द्र पाण्डेय

पिछले कुछ दिनों में मिली असफलताओं के कारण पर्यवेक्षकों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या नरेन्द्र मोदी सरकार अब उस क्षेत्र में लड़खड़ा रही है, कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वह चमक खत्म हो रही है। ये पहली बार है जब मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

2014 में में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी . सत्ता में आने के बाद से मोदी को यदि किसी नीति में सबसे ज्यादा प्रशंसा मिली तो वो है विदेश नीति। विदेशों में उनकी बैठकों में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को भी प्रभावित किया है। वैश्विक मंदी के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि और महामारी के बाद की स्थिर अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों के विशेषज्ञों द्वारा काफी सराहना मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मिली असफलताओं के कारण पर्यवेक्षकों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या नरेन्द्र मोदी सरकार अब उस क्षेत्र में लड़खड़ा रही है, कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वह चमक खत्म हो रही है। ये पहली बार जब मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। झटका तब लगा जब भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया, जो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि अमेरिकी धरती पर सिख चरमपंथी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत की कथित संलिप्तता सामने आई। भारत ने कनाडा के आरोपों को चुनौती दी, लेकिन अमेरिका के आरोपों के बाद मामले की गहन जांच करने पर सहमत हो गया।

मोदी की मॉस्को यात्रा इसी पृष्ठभूमि में हुई। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी लगातार तीसरी अवधि की पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा थी। लेकिन यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा वाशिंगटन में यूक्रेन के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाने और रूस को अलग-थलग करने के उद्देश्य से आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। यह कहना मुश्किल है कि मोदी की मॉस्को यात्रा गलत समय पर हुई थी या जानबूझकर यह दिखाने के लिए की गई थी कि भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं अमेरिका द्वारा तय नहीं की जाती हैं। जैसा कि अनुमान था, इसके कारण अमेरिका और यूक्रेन की ओर से विरोध प्रदर्शन हुए।

जब यूक्रेन में एक स्कूल की इमारत पर मिसाइल गिरी और कई बच्चे मारे गए, तो मामला और बिगड़ गया। मिसाइल का स्रोत तो पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि रूस ने इसे दागा था। यह त्रासदी उस समय घटित हुई जब मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा गईं।

भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि संघर्ष के दौरान 'रणनीतिक स्वायत्तता' के लिए कोई जगह नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता इन दिनो मास्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है।' भारतीय अधिकारियों ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि यह अपेक्षा करना अवास्तविक है कि भारत (शेष पृष्ठ 2 पर)

राहुल बोले मोदी से हमदर्दी, सैम ने कहा पप्पू नहीं हैं राहुल

हर्षित पाण्डेय

बीजेपी और पीएम मोदी ने जो डर फैलाया था. छोटे कारोबारियों , एजेंसियों पर दबाव, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया. उन्हें यह डर फैलाने में वर्षों लग गए और वे कुछ ही सेकंड में गायब हो गए... संसद में, जब मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि श्री मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध, यह सब अब खत्म हो गया है, यह सब अब इतिहास है...।

राजनीति में एक दल का नेता दूसरे दल पर टीका टिप्पणी ना करें तो उनकी सियासत की दुकान कैसे चलेगी। लेकिन यदि कोई राजनीतिक शख्सियत किसी गैर राजनीतिक दल पर निशाना साधे तो संदेश को समझना जरूरी हो जाता है। भारत में एक ऐसा ही संगठन है , राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन उसका राजनीतिक झुकाव पूर्ण रूपेण भाजपा की तरफ होता है. इसलिए तो राजनीति में ना होते हुए भी यह सियासी हमलों के केंद्र में होता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार आरएसएस की विचारधार पर हमला बोलते रहते है .

हाल में ही राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका प्रवास पर आरएसएस की विचारधार पर तीखे हमले किए। राहुल ने कहा, आरएसएस कहता है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों से हीन हैं। कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से हीन हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों से हीन हैं और कुछ समुदाय अन्य समुदायों से हीन हैं... हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है...आरएसएस की विचारधारा तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी है, ये हीन भाषाएं हैं... इसी बात को लेकर लड़ाई है...ये आरएसएस के लोग भारत को नहीं समझते. बीजेपी को यह समझ में नहीं आता कि यह देश सबका है...भारत एक संघ है. संविधान में साफ लिखा है...भारत यानी भारत एक संघ राज्य है, इतिहास, परंपरा, संगीत और नृत्य...बीजेपी कहती हैं कि यह संघ नहीं है, यह अलग है... । अब चुनाव के बाद कुछ बदल गया है. कुछ लोगों ने कहा 'डर नहीं लगेगा अब, डर निकल गया अब'...मेरे लिए यह दिलचस्प है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने जो डर फैलाया था. छोटे कारोबारियों , एजेंसियों पर दबाव, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया. उन्हें यह डर फैलाने में वर्षों लग गए और वे कुछ ही सेकंड में गायब हो गए... संसद में, जब मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि श्री मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध, यह सब अब खत्म हो गया है, यह सब अब इतिहास है...।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा टेक्सास में इंडियन डायसपोरा को संबोधित करते हुए ने राहुल गाँधी की तारीफ करते हुए कहा, 'राहुल गाँधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करना है। मैं आपको बता दूँ कि वह 'पप्पू' नहीं हैं, वह उच्च शिक्षित हैं, वह किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं और कई बार उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है।' पित्रोदा ने आगे कहा कि राहुल गाँधी की सोच का कोई तोड़ नहीं है। उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको गलत दिखाने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन कुछ नहीं हुआ।

टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, शिव और बुद्ध जैसे विषयों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने देवता , शिव और बुद्ध को भी समझाया हालाँकि मुझे कुछ समझ नहीं आया विडियो में आप भी सुनिए शायद आपको समझ आये . मुझे कॉमेंट्स जरुर करियेगा . खैर उन्होंने देवता शब्द के अर्थ को समझाते हुए कहा कि देवता वह व्यक्ति होता है जिसकी अंदरूनी भावनाएं और बाहरी अभिव्यक्ति एक समान होती हैं। उन्होंने बताया कि एक पारदर्शी और साफ दिल का व्यक्ति ही देवता कहलाने योग्य है।

राहुल के अनुसार, जो व्यक्ति बिना किसी डर या झिझक के अपनी सोच को खुलकर सामने रखता है, वही देवता है। राहुल गांधी ने शिव के विचार पर चर्चा करते हुए कहा कि शिव विनाशक के रूप में अपने अहं, (शेष पृष्ठ 2 पर)

शारीरिक और मानसिक आहार

हमारे स्वास्थ्य के एक सिक्के के दो पहलू

डॉ अनिल गुप्ता
MBBS, Ms, PhD, FFM
फाउंडर-पॉजीटिव हेल्थ जोन

स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से भी है। जहां हम अपने शारीरिक के लिए खाने-पीने पर ध्यान देते हैं, तो वहीं हमारे द्वारा लिए जाने वाले मानसिक आहार का भी हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही गहरा असर होता है। शारीरिक और मानसिक आहार दोनों मिलकर हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, और इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

इस लेख के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक आहार के आपसी संबंधों को समझने और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दोनों हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

शारीरिक आहार का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव

शारीरिक आहार वह भोजन और पेय होता है जिसे हम अपने शरीर में डालते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, विकास, और मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं।

एक स्वस्थ शारीरिक आहार के प्रमुख घटक

1. **संतुलित आहार**- ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर आहार हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि हमारे आहार में पोषण की कमी या असंतुलन होता है, तो इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2. **पर्याप्त पानी पीना**- पानी हमारे शरीर के पाचन, रक्त संचार, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी की कमी से शरीर में थकान और मानसिक अवरोध हो सकता है।
3. **सही मात्रा में खाना**-खाने की सही मात्रा का ध्यान रखने से वजन, शुगर और पाचन तंत्र को संतुलित रखा जा सकता है। जरूरत से ज्यादा या कम खाने से शरीर में गड़बड़ हो सकती है।
4. **आंतों का स्वास्थ्य**-एक स्वस्थ आंत पाचन में मदद करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाती है। दही जैसे प्रोबायोटिक और सब्जियों जैसे फाइबर युक्त भोजन आंत के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

यदि हमारा शारीरिक आहार संतुलित नहीं है, तो इससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य (शेष पृष्ठ 2 पर)

मानसिक आहार का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव

मानसिक आहार वह विचार, भावनाएं और सूचनाएं हैं जिन्हें हम अपने मन में रोज़ भरते हैं। जिस तरह से हमारा शारीरिक आहार हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उसी तरह से मानसिक आहार हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में सुशासन के 8 माह

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सायछत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वंनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय 'आपका अच्छा गांव'। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई। 'पीएम जनमन योजना' की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है।

इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। श्री साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। (शेष पृष्ठ 2 पर)

दोगलापन की भी हद होती है मुख्य न्यायाधीश की गणेश पूजा में प्रधानमंत्री का होना 'लोकतंत्र पर खतरा' पीएम की इफ्तार पार्टी में सीजेआई का जाना 'सेकुलरिज्म'

गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुँचते है । सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने प्रधानमंधी का स्वागत किया। बाद में सबने हाथ में थाल लेकर गणेश भगवान की पूजा-अर्चना की, ये दृश्य सामान्य हिंदू के लिए अभिभूत करने वाला था लेकिन लिबरलों के लिए ये किसी जख्म से कम नहीं । उनके लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान सब खतरे में आ गया है। कहा जा रहा है कि अब सीजेआई और प्रधानमंत्री के बीच के रिश्ते खुलकर दिखने लगे हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि उन्हें अदालत से न्याय मिल सकेगा या नहीं।

रोना रोने वालों में पहला नाम आरफा खानुम शेरवानी का है। उन्हें सीजेआई के घर में पीएम मोदी को आरती करता देख उनका कलेजा फट गया । उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा- 'इंसान जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा।' उनके हिसाब से यहाँ 'इंसान' सीजेआई हैं और 'जालिम' पीएम मोदी हैं। अगर पीएम मोदी ही सीजेआई से अच्छे संबंध रखेंगे तो फिर आखिर उन लोगों की कौन सुनेगा।

अगला नाम नेहा सिंह राठौड़ का है जिन्होंने आरती की घंटी की तुलना खतरे की घंटी से करते हुए

नेहा राठौड़ कहती हैं- 'जज साहब के घर गणपति पूजा की आरती में लोकतंत्र के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है।' इस तरह अशोक धावले सीजेआई के घर पीएम मोदी को पूजा करते हुए देख कहते हैं

अब न्यायाधीश चंद्रचूड़ को उनकी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में पोस्ट मिलेगी, वो राज्यपाल बनेंगे या फिर अडानी बोर्ड के डायरेक्टर या हो सकता है अगले कानून मंत्री ही बन जाएँ। प्रशांत भूषण इस वीडियो को देख कहते हैं- हैरानी है कि मुख्य न्यायाधीश ने मोदी को अपने आवास पर प्राइवेट मीटिंग के लिए आने दिया। बहुत बुरा संदेश जाएगा कि जिस न्यायपालिका का काम मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है वह सरकार के दायरे में काम करे। प्रशांत भूषण बताते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी होनी चाहिए।

लिबरल पत्रकार और लिबरल वकीलों के बाद कुछ राजनेता भी हैं जिन्हें पीएम मोदी द्वारा सीजेआई के घर जाने पर आपत्ति हो रही है। शिवसेना के संजय राउत कहते हैं कि उनकी पार्टी का मामला कोर्ट में हैं जिसमें दूसरी पार्टी केंद्र सरकार हैं ऐसे में वो कैसे सोचें कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसी तरह पूर्व कॉन्ग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी अपने ट्वीट में इस मुद्दे को उठाती हैं पूछती हैं कि क्या जो महाराष्ट्र का मामला कोर्ट में है उसमें फैसला आ जाएगा या चुनाव आने तक उसे टाला जाता रहेगा। पर दिलचस्प बात यह है कि इसी लिबरल जमात को इफ्तार पार्टी से समस्या नहीं होती । अगर देश का प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी का आयोजन कराए और देश के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होने जाएँ तब इन्हें डर नहीं सताता । यह बात कोई काल्पनिक नहीं है। साल 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उनके घर पर इफ्तार पार्टी होस्ट की गई थी और उस समय उनकी मेहमानों में एक चेहरा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन का भी था। (शेष पृष्ठ 2 पर)

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:45 PM Page 2

विधायक मोतीलाल साहू ने किया रिम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन

राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र उरला मे उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से रायपुर के प्रतिष्ठित निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा एक अस्पताल उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू द्वारा किया गया । इस अवसर पर विधायक साहू ने कहा कि यह क्षेत्र विविधताओ से भरा हुआ है । उददयोग होने के वजह यहाँ लगभग देश के सभी प्रांत के लोग रहते है जिनमे श्रमिक भाइयों की संख्या ज्यादा है । देश और प्रदेश के विकास मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र मे स्वास्थ्य एक समस्या है । अक्सर आर्थिक कमजोरियों के कारण श्रमिक भाई समुचित इलाज से वंचित रह जाते है । रिम्स मेडिकल कालेज द्वारा अपनी इस ब्रांच से निश्चित रूप से इस क्षेत्र के साथ साथ आस पास के अन्य गाँवों को भी फायदा पहुंचेगा।

कार्यक्रम मे नगर निगम मे नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश साहू , पार्षद बेदराम साहू ,एसोसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष , आश्विन गर्ग, जनरल सेक्रेटेरी विक्रम जैन,जॉइन सेक्रेटरी नीरज अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं अस्पताल के डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

रिम्स के डायरेक्टर डॉ के के वाधवा ने कहा कि हम यहाँ पर ओपीडी पूर्णत: निशुल्क रखे है एवं जाँच आदि को बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर रखा हुआ है जैसे एक्स-रे मात्र 50 रु मे सोनोग्राफी 200 रु । अस्पताल मे 24 × 7 डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध रहेगे । इमरजेंसी के लिए मिनी ऑपरेशन थियेटर के साथ 6 बिस्तर की भी व्यवस्था है । जरूरत पड़ने पर मरीजों को हमारे कालेज मे शिफ्ट किया जाएगा जहां इलाज सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्थ कार्ड द्वारा किया जाता है एवं यदि कार्ड नहीं है तो बहुत ही न्यूनतम दरों पर सुविधाएं दी जाती है ।

उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष आश्विन गर्ग ने बताया कि हर इंडस्ट्री मे स्वास्थ्य की सुविधा देना संभव नहीं हो पाता । प्राथमिक उपचार के साथ साथ आवश्यकता थी कि आपात स्थिति अथवा गंभीर बीमारियों के लिए कोई अच्छा अस्पताल हो जो काम दरों पर इलाज सुविधा मुहैया करा सके। रिम्स प्रबंधन ने इस पर हमे अस्वस्त किया है । इस अस्पताल के खुलने से श्रमिक भाइयों और उनके परिजनों के साथ साथ आस-पास के ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचेगा यहाँ पर कोई भी जन सामान्य आकर यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का लाभ ले सकता है ।

रिम्स के डीन डॉ गंभीर सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण , स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव की वजह से की प्रकार की बीमारिया होती है जिनका सही समय पर परीक्षण होना जरूरी होता है । इसके लिए हमार सतत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एसोसिएशन के सहयोग एवं विध्यक जी के मार्गदर्शन पर चलता रहेगा । इस सेंटर के खुलने से निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा । हम अभी यहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कर रहे है गंभीर परिस्थिति के लिए हम उन्हे पाने टरशरी सेंटर अर्थात रिम्स मेडिकल कालेज ले जाकर इलाज करेंगे ।

आरईसी ने दिया साइंस कालेज को बैडमिंटन कोर्ट की सौगात

रायपुर। छत्तीसगढ़ से श्रेयांश जायसवाल और आकर्शी कश्यप जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी और निकल सके इसी क्रम में भारत की अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड ने रायपुर के नागार्जुन साइंस महाविद्यालय रायपुर में बैडमिंटन कोर्ट का उदघाटन किया . इस अवसर पर आरईसी लिमिटेड के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा, 'हम राष्ट्रीय खेल विकास कोष के साथ मिलकर अपनी सीएसआर द्वारा भारत में बैडमिंटन, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे है।'

नॉमिनी डायरेक्टर डॉ गंभीर सिंह ने कहा की पढ़ाई के साथ साथ खेल जरुरी है बैडमिंटन जैसे खेल न केवल फिजीकली फिट रखते है बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और एकाग्रता बढाने में भी सहायक होते है .

प्राचार्य अरुण मिश्रा ने आरईसी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की इस प्रयास से राज्य के उन गरीब छात्रो को लाभ मिलेगा जो आर्थिक कमजोरियों के चलते बैडमिंटन खेलने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते थे .

बीएई के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा अब प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने में मदद मिलेगी .

लाईफ फ़ोर्स एनर्जी को समझ लीजिये स्वास्थ्य समझ आ जायेगा

रायपुर। वर्तमान समय में लोगों के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो गया है खुद को स्वस्थ रखना। स्वस्थ होने का अर्थ सिर्फ बाहरी शारीरिक नहीं बल्कि आंतरिक शारीरिक अंगों को और मानसिक रूप से भी। क्योंकि बिगड़ी जीवनशैली, खानपान, नींद पूरी ना होने, प्रदूषण आदि जैसे विभिन्न कारणों से आज सम्पूर्ण भारत ही नहीं विश्व भर में लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहें हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे कितने गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। इसको गहराई से अध्ययन करने की भी जरूरत है। दवा रोग उत्पन्न होने के बाद दिया जाता है, किन्तु दवा उसको प्राकृतिक रूप से पुन: की स्थिति में नहीं ले जा सकती है। हां रोग को बढ़ने से जरुर रोक देती है अथवा प्रभाव को कम कर सकती है।

ऊर्जा शरीर एवँ उसका ज्ञान और उसका संतुलन, आपके जीवन में ,आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चक्र विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपके ऊर्जा शरीर को भौतिक शरीर के साथ संतुलित रखता है। आपके जीवन को हर तरीके से सार्थक बनाता है। वैदिक विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर मे सात चक्र होते है जो लाइफ फोर्स एनर्जी के केंद्र होते है।ये चक्र ही हमारे भौतिक,भनात्मक और आध्यात्मिक वैलनेस के लिए उत्तरदायी होते है।प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट रंग,ध्वनि और तत्व से जुड़ा होता है।जब ये चक्र सन्तुलित होते है एवँ इनमें लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह भी सन्तुलित होता है तब हम स्वस्थ और वैलनेस की अवस्था मे होते है ,लेकिन इनके अंतुलन से हम अस्वस्थता की ओर जाते है।

उक्त बातें डॉ अनिल गुप्ता ने प्रशासनिक एकेडमी नवा रायपुर में आयुष चिकित्सको के मध्य एक सेमिनार में लाइफ फोर्स एनर्जी और हमारा स्वास्थ्यविषय पर व्याख्यान देते हुए कहा।

सियासी खेल में विस्थापित होते आदिवासी

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार हसदेव जंगल की कटाई की जा रही है नो गो एरिया घोषित होने के बावजूद जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है . आदिवासी समाज निरंतर बहुमूल्य वनों की कटाई का विरोध किया जा रहा है . सम्बन्धित अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है लेकिन वे अपने प्रशासनिक पद का दुरूपयोग करते हुए अवैधानिक रूप से जंगलों की कटाई की अनुमति दिये है जिससे आस पास के गाँवों की जीवन शैली बिगड़ गई है और ग्रामीण विस्थापन को मजबूर हो गए .

हमर राज पार्टी ने सरकार के ऊपर उद्योगपतियों को व्यापारिक लाभ पहुचाने का गंभीर आरोप लगाया. पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बी एस रावट और राष्ट्रीय महासचिव विनोद नागवंशी ने लाईफ वर्सिटी से बात करते हुए बताया कि नो गो एरिया होने के बाद भी जल,जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है . जब छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा 26 जुलाई 2022 को हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लाक रद्द किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था तो सरकार उसका पलन क्यों नहीं कर रही . पदाधिकारी द्वय ने सवाल उठाया की वर्तमान में खदान एरिया 1250 हेक्टेयर है जिसमे 700 हेक्टेयर खदान एवं 100 हेक्टेयर में वाशरी और अन्य कार्य के लिए आरक्षित है . नियमत = 1 हेक्टेयर में अधिकतम 250 पौधे लगाए जा सकते है. खदान में 12 लाख पौधे लगाने सम्बन्धित जानकारी पूर्णतया; भ्रामक है .

विनोद नागवंशी कहते है कि असुविधा,प्रताड़ना एवं ग्राम के पारंपरिक आस्था के विपिरित परिस्थिति के कारण आकस्मिक मौत हो रही है . जन्मदर घट रही है और मृत्युदर बढती जा रही है. रावटे बतलाते है कि कोल ब्लाक 15 वर्षो के लिए उत्खनन का समय अवधि खत्म नहीं हुई है वर्तमान में 140 मिलियन कोयला खनन होना था , अभी 82 मिलियन टन कोयला खनन हुआ है . 58 मिलियन टन कोयला गलत माइनिंग के कारण फेस में दबा है .

बता दे कि हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव-विविधता से परिपूर्ण है. हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का केचमेंट है जो जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास बुझाता है. यह वन क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन है जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगल, झारखंड के पलामू के जंगलों से जोड़ता है. यह हाथी जैसे 25 महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है.

2010 से शुरू हुआ हसदेव का दोहन

2010 में हसदेव क्षेत्र में खदान खोलने का सिलसिला शुरू हुआ तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसकी स्वीकृति दी और सूबे में बैठी भाजपा ने इसका प्रस्ताव भेजा. इसी वर्ष केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए नो-गो एरिया घोषित किया था. फिर इसी मंत्रालय के वन सलाहकार समिति श्रेष्ट ने खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट और केते बासन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दी थी, जिसे साल 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने निरस्त भी कर दिया.

मानव हाथी संघर्ष की दी गई थी चेतावनी- भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई. जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि हसदेव अरण्य समृद्ध, जैवविविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है. इसमें कई विलुप्त प्राय वन्यप्राणी आज भी मौजूद है. इस रिपोर्ट में एक चेतवानी भी दी गई है कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को संभालना लगभग नामुमकिन होगा.

अडानी की कंपनी मिली खनन की अनुमति-

इन सबके बावजूद परसा कोल ब्लॉक का काम शुरू कर दिया गया. यह आवंटन राजस्थान सरकार को दिया गया. राजस्थान सरकार की राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी ने इसका एमडीओ अडानी को दे दिया और अब अडानी की कंपनी यहां से कोल परिवहन का काम करती है. जब इस खदान को खोला गया तब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की रमन सिंह की सरकार थी. इसके बाद शुरू हुआ सियासी खेल.

कांग्रेस सरकार में शुरू हुई पेड़ों की कटाई

कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में आ गई. ग्रामीणों को भरोसा हुआ कि अब सरकार खदान नहीं खुलने देगी और पेड़ नहीं कटेंगे लेकिन कांग्रेस की सत्ता में भी प्रशासन ने बल पूर्वक सितंबर 2022 में पेड़ों की कटाई की. 3 हेक्टेयर के 8000 पेड़ काटे गए. इस दौरान भाजपा के नेताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया. तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव भाजपा ने किया और खुद को पर्यावरण प्रेमी बताया. हालांकि बाद में टीएस सिंहदेव खुद हसदेव के जंगल पहुंचे और आदिवासियों से मिलकर एक पत्ता भी नहीं तोड़े जाने का वादा किया. इसके बाद हसदेव में पेड़ों की कटाई रोक दी गई.

विष्णुदेव साय के शपथ लेते ही पेड़ कटने शुरू-

वक्त गुजरा और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी. 13 दिसंबर को भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया. मंत्रीमंडल का गठन भी नहीं हुआ लेकिन शपथ ग्रहण के सातवें दिन ही हसदेव में पेड़ कटाई फिर शुरू हो गई. इस बार 91 हेक्टेयर के 15307 पेड़ों की कटाई हुई. खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने वाले भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध ली.

फर्जी ग्राम सभा बनाकर पेड़ काटने की अनुमति देने का आरोप

हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल खदान खोलने को लेकर कई गतिरोध है. एक तरफ जहां ये जंगल जैव विविधता के कारण नो गो एरिया घोषित हैं तो वहीं दूसरी और अनुसूचित क्षेत्र होने के कारन यहां की ग्राम पंचायतों को पेसा कानून का विशेषाधिकार भी मिला है. इन अधिकारों के तहत भी ग्रामीण इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि पेशा कानून का पालन किया गया है.

नो गो एरिया होने के बाद भी जल,जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है . जब छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा 26 जुलाई 2022 को हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लाक रद्द किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था तो सरकार उसका पलन क्यों नहीं कर रही .

विनोद नागवंशी
राष्ट्रीय महासचिव ,हमर राज पार्टी

क्या है पेसा कानून

भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी लेकिन यह महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है. इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया जिसे 24 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया. यह कानून पेसा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अंग्रेजी में इस कानून का नाम प्रोविजन आफ पंचायत एक्टेशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 है.

क्या है कोल बेरिंग एक्ट

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 8 जून, 1957 भारत के आर्थिक हित में कोयला खान उद्योग और उसके विकास पर व्यापक लोक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसी भूमि का जिसकी खुदाई न हुई हो या जिस पर कोयला भण्डार पाए जाने की संभावना हो या उसमें या उस पर राज्य द्वारा अर्जन करने के लिए, किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर उपबंध करने के लिए बनाया गया अधिनियम है. कोल बेरिंग एक्ट के पूरे प्रोविजन काफी बड़े हैं जिसमे कोयला धारकों को कई अधिकार दिए गए हैं.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:45 PM Page 3

विकसित भारत के लिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव

रवनीत सिंह बिट्टू
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री

हमारे देश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक प्रकाश-पुंज की तरह है, जो विकसित भारत की दिशा में हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। अब यह क्षेत्र केवल अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ता भर नहीं रह गया है, बल्कि तेजी से भारत की विकास गाथा का आधार बनता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में नीतियों, पहलों और बुनियादी ढांचे के विकास के बेहतरीन मिश्रण ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। वर्तमान में भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर वाली समृद्ध अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 में देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना है।

भारत में हो रहे बदलावों के मूल में इसकी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता है, जो हमारे किसानों को विभिन्न प्रकार की विशिष्ट फसलें उगाने में सक्षम बनाती है। दालें, मोटे अनाज, दूध, गेहूं, चावल तथा फलों और सब्जियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश होने के रूप में, भारत के पास मूल्य वर्धन के लिए संसाधनों का अद्वितीय आधार मौजूद है। हमारे मेहनतकश किसानों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित इस कृषि प्रचुरता ने नवाचार और उद्यमिता के दौर को जन्म दिया है, जिससे उन्नतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उदय हुआ है।

यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का आधार बन चुका है, जो रोजगार के अवसरों के सृजन, तकनीकी प्रगति और बाजार के नए अवसरों के निर्माण के माध्यम से विकास को गति दे रहा है। भारत शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी और सबसे युवा कामकाजी आबादी होने का भी दावा करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को और बढ़ावा मिलता है। उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, इस उद्योग ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और किसानों को उनके प्रयासों के लिए बेहतर रिटर्न दिलाना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे-जैसे विकसित हो रहा है, यह न केवल गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर खरा उतर रहा है, बल्कि वैश्विक उपभोक्ताओं की लगातार बदलती पसंद और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पेशकशों में विविधता भी ला रहा है। इस प्रकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बीच का घनिष्ठ सामंजस्य आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली साधन का रूप ले चुका है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे किसान और कृषि देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के कृषि उत्पाद दुनिया के कोने- कोने में संवर्धित मूल्य और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। ऊर्जावान और युवा कार्यबल द्वारा समर्थित इस एकीकरण के माध्यम से, हम इस सशक्त, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के उद्भव का साक्षी बन रहे हैं जो भारत को एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने के लिए तत्पर है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, कोविड-19 महामारी ने इस क्षेत्र के प्रभावशाली लचीलेपन को दर्शाया, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के अनुरूप तेजी से अनुकूलित हुआ। रेडी-टू-ईट, रेडी-टू-कुक और मूल्य-वर्धित उत्पादों की ओर धीरे-धीरे बदलाव ने खाद्य सुरक्षा और पोषण में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने, सुविधा प्रदान करने, लंबी शेल्फ लाइफ और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आवश्यक है। यह किसानों के लिए बेहतर दामों की प्राप्ति भी सुनिश्चित करते हुए और बाजार के अवसरों में वृद्धि करते हुए, जीडीपी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और आजीविका में सहायता प्रदान करता है।

इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) सबसे अग्रणी है, जो पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है। यह पहल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करके और खेत से लेकर खुदरा तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करके इस क्षेत्र को बदल रही है। इन प्रयासों को पूर्णता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण और विपणन में सहायता के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देती है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) वृद्धिशील बिक्री से जुड़े वित्तीय पुरस्कारों की पेशकश करके घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात वृद्धि को और बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये का विशेष अवसंरचना कोष इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समन्वित दृष्टिकोण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को उन्नत बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति को रेखांकित करता है, जो मजबूत, एकीकृत और दूरंदेशी विकास पथ सुनिश्चित करता है।

भारत में हो रहे बदलावों के मूल में इसकी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता है, जो हमारे किसानों को विभिन्न प्रकार की विशिष्ट फसलें उगाने में सक्षम बनाती है। दालें, मोटे अनाज, दूध, गेहूं, चावल तथा फलों और सब्जियों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश होने के रूप में, भारत के पास मूल्य वर्धन के लिए संसाधनों का अद्वितीय आधार मौजूद है। हमारे मेहनतकश किसानों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित इस कृषि प्रचुरता ने नवाचार और उद्यमिता के दौर को जन्म दिया है, जिससे उन्नतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उदय हुआ है।

भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसका जनसांख्यिकीय लाभांश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नई ऊंचाइयों को छूने के अनूठे और अभूतपूर्व अवसरों का सृजन करता है। सरकार के महत्वपूर्ण कर संबंधी प्रोत्साहनों, कारोबार करने में सुगमता की सुव्यवस्थित पहल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित दूरदर्शी व्यवसाय समर्थक सुधारों ने निवेश और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है। यह सहयोगपूर्ण परिदृश्य न केवल वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है बल्कि भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और विस्तार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है।

वर्ष 2023 में पिछले संस्करण की शानदार सफलता के बाद, मंत्रालय 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में खाद्य उद्योग के हर पक्ष से जुड़े हितधारक विचारों का आदान-प्रदान करने, अवसरों का अन्वेषण करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने के लिए एक साथ आएंगे। यह एक अनोखा सम्मेलन होगा जिसमें दुनिया भर के खाद्य इकोसिस्?टम से जुड़े निर्माता, उत्पादक, निवेशक, नीति-निर्माता और संगठन शामिल होंगे।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक ऐसा मंच है, जहां हितधारक नवाचारों का अन्वेषण करने, साझेदारी बनाने और टिकाऊ खाद्य भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। आइए, हम अपने सामने मौजूद अवसरों का लाभ उठाएं तथा अधिक समृद्ध और लचीली खाद्य प्रणाली की दिशा में ऐसी यात्रा की शुरुआत करें, जो मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को लाभान्वित करे। सामंजस्य के इस दौर में, हम न केवल एक उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य के साझा विजन को भी अंगीकार कर रहे हैं जहां नवाचार, स्थिरता और समृद्धि हमारे देश के कोने-कोने का उत्थान करे।

बढ़ता जानलेवा प्रदूषण गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके।

चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के हाल के अध्ययन में वायु प्रदूषण की बढ़ती विनाशकारी स्थितियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि अत्यंत चिन्तातनक है। भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को बीस से तीस फीसदी कम किया जा सके। लेकिन विडम्बना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान को निरन्तर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फैंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है।

प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में गत दो-तीन साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक हैं पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है।

प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता।

क्या मोदी विदेश नीति में वो चमक नहीं रही?

यूक्रेन युद्ध को प्राथमिकता देने के लिए अपने राष्ट्रीय हित का त्याग कर देगा। उधर मोदी ने उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन से की गई अपनी टिप्पणी को मॉस्को में फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध के ज़रिए मुद्दों को सुलझाने का समय नहीं है। लेकिन इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा।

भारत ने जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा की योजना बनाकर अपनी दिशा में एक और सुधार किया। एक पूर्व भारतीय राजदूत ने कहा, यूक्रेन से अधिक, इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका को खुश करना था, जो मोदी की रूस यात्रा और वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के समय के मेल से बेहद नाराज था।

इन दोनों यात्राओं से पहले एक और झटका लगा, जब क्षेत्र में भारत की सबसे करीबी सहयोगी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया गया। उनके अचानक हटाए जाने से नई दिल्ली पूरी तरह से अचंभित रह गया और इससे उसकी सीमा पर गंभीर सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न हो गईं तथा ढाका के साथ उसके भविष्य के संबंधों को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न हो गईं। लेकिन इससे मोदी का ध्यान अपनी योजनाबद्ध पूर्वी यूरोपीय यात्राओं पर जाने से नहीं हटा।

मोदी की यूक्रेन यात्रा को एक शांति मिशन के रूप में देखा गया तथा भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका को एक संभावित शांति निर्माता के रूप में देखा गया, क्योंकि उन्हें रूसी राष्ट्रपति का भी विश्वास प्राप्त था।

लेकिन इससे पहले कि वह कीव का दौरा कर पाते, यूक्रेन ने रूस पर अपना हमला तेज़ कर दिया और रूसी क्षेत्र के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पुतिन का रुख़ और सख्त हो गया और उन्होंने घोषणा की कि वह अब शांति के पक्ष में नहीं हैं।

कीव में बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ज़ेलेंस्की ने मोदी द्वारा वार्ता के दौरान रखे गए सभी प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया, जिसके कारण भारतीय टिप्पणीकारों ने उन्हें यूक्रेन में शांति के बारे में 'मूर्ख', 'बचकाना' और 'कपटपूर्ण' बताया। हालांकि, यूक्रेन में मोदी के असफल शांति मिशन को उचित ठहराने के लिए जो भी बातें कही जा रही हैं, उनसे इतर, भारत की विदेश नीति में हाल की असफलताओं से उत्पन्न बड़ा सवाल जल्द ही शांत होने वाला नहीं है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गत मना कि भारत के सामने एक 'विशेष चीन समस्या' है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चार साल से चल रहा सैन्य गतिरोध और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति चीनी निवेश की जांच जैसे एहतियाती उपायों की मांग है.

बता दें कि अप्रैल-मई 2020 में एलएसी पर गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध छह दशक के निचले स्तर पर हैं. उन्होंने कहा कि भारत के सामने एक चीन समस्या है, एक विशेष चीन समस्या, जो दुनिया की सामान्य चीन समस्या से अलग है.

चीन के साथ व्यापार, निवेश और विभिन्न प्रकार के आदान-प्रदान से निपटने के दौरान बुनियादी बातें पटरी से उतरने लगती हैं.

मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास चीन से निवेश है या नहीं. इसका जवाब हां या नहीं नहीं है. या जांच का उचित स्तर क्या होना चाहिए, आपको इसे कैसे संभालना चाहिए. भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने तर्क दिया था कि व्यावसायिक प्रस्तावों में राष्ट्रीय सुरक्षा संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. अब मोदी गठबंधन की सरकार है कितना और कैसा मूल्यांकन होगा इस पर नज़र रहेगी .

राहुल बोले मोदी से हमदर्दी,सैम ने कहा पप्पू नहीं हैं राहुल

संरचना और मान्यताओं का विनाश करते हैं। यही विचार भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। राहुल ने कहा कि हमारी राजनीति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं? आप अपने डर, लालच या महत्वाकांक्षाओं को दबाकर दूसरों के डर और महत्वाकांक्षाओं पर कैसे फोकस करते है.

अब इन बयानों के की नेताओं सहित आम जनता में भी चर्चाये हो रही है लोगो का मानना है कि इससे राहुल गाँधी की तारीफ की जगह उनका और भी मखौल उड़ रहा है। लोग कहते हैं कि इस तरह के बयान देकर तो कांग्रेसी सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो भी मानते हैं कि लोग राहुल गाँधी को क्या समझते हैं और उन्हें सिर्फ उनका बचाव करना है।

शारीरिक और मानसिक आहार , हमारे स्वास्थ्य के एक सिक्के के दो पहलू

स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, पोषक तत्वों से भरपूर आहार हमारे शरीर की ऊर्जा, प्रतिरक्षा और जीवनशक्ति को बढ़ाता है।

एक स्वस्थ मानसिक आहार के प्रमुख घटक

1. **सकारात्मक सोच**-हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक सोच, जैसे आत्म-संदेह, निराशा या तनाव, हमारे दिमाग पर बुरा असर डालती है और इससे अवसाद, चिंता और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2. **भावनात्मक संतुलन**-भावनाओं को सही ढंग से समझना और प्रबंधित करना हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। भावनात्मक समझ से हम तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
3. **सूचना का सही चयन**- सोशल मीडिया और न्यूज़ जैसे स्रोतों से हमें रोज़ ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं। नकारात्मक या भ्रामक सूचनाएं हमारे मन को विचलित कर सकती हैं और चिंता पैदा कर सकती हैं। इसलिए हमें सकारात्मक और शिक्षाप्रद सूचनाओं का चयन करना चाहिए।
4. **आत्म-संवाद**- हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं, यह हमारी आत्म-छवि और आत्मविश्वास पर असर डालता है। सकारात्मक आत्म-संवाद से हम अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, जबकि नकारात्मक आत्म-संवाद से मानसिक तनाव हो सकता है।
5. **मानसिक आराम**- जिस तरह शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। ध्यान, योग और प्रकृति में समय बिताने जैसी गतिविधियाँ मानसिक आराम प्रदान करती हैं, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है।

अगर हम अपने मानसिक आहार की अनदेखी करते हैं—नकारात्मक विचार, तनावपूर्ण सूचना या विषाक्त सामाजिक संबंधों को अपने जीवन में लाते हैं—तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालता है। वहीं, सकारात्मक और स्वस्थ मानसिक आहार से हम मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं।

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।

सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।

दोगलापन की भी हद होती है मुख्य न्यायाधीश की गणेश पूजा में प्रधानमंत्री का होना 'लोकतंत्र पर खतरा' पीएम की इफ्तार पार्टी में सीजेआई का जाना 'सेकुलरिज्म'

आज लोकतंत्र को खतरे में बताकर चिल्लाने वालों को शायद तब सब कुछ सही लगा हो। तब द्वद्वन लोगों को डर नही सताया था । उस समय भी नहीं जब सीजेआई ही प्रधानमंत्री के घर आकर उनसे हँस-हँस कर बात कर रही हैं तो फिर इंसाफ कौन करेगा।

इनका ये डर आज सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 'नरेंद्र मोदी' हैं और वो हिंदू धर्म को मानने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा कर रहे हैं।

लिबरलों के हिसाब से तो शायद सीजेआई का धर्म हिंदू है तो उन्हें मन से नास्तिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने धर्म का पालन करेंगे तो इस जमात को हमेशा यही लगेगा कि जो शख्स पूजा पाठ करता है वो कैसे न्याय कर पाएगा! लेकिन वही व्यक्ति बैठकर घर में इफ्तार पार्टी कर दे तो उसकी विश्वसनीयता इनकी नजरों में दुगनी बढ़ जाएगी, उसमें न्याय की क्षमता आ जाएगी, उसके सेकुलरिज्म के कसीदे पढ़ें जाएँगे।

इन लिबरलों को जानकारी होनी चाहिए कि आज जिस लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताकर ये लोग सीजेआई के घर होती पूजा और उसमें शामिल हुए पीएम का विरोध कर रहे हैं वहीं संविधान देश के नागरिकों को अनुच्छेद 25 के तहत अपने-अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। अनुच्छेद 25 (1) में उल्लिखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

अब ये जमात ये तो नहीं कह सकती न कि देश का पीएम बनने से और सीजेआई बनने से देश की नागरिकता छिन जाती हैज सच तो यही है कि जो अधिकार एक नागरिक के होते हैं वही अधिकार पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भी हैं।

ऐसे में अगर ये दोनों लोग अपने इन अधिकारों से वाकिफ हैं और इन्हें अपने धर्म का आचरण करने में समस्या नहीं है तो जाहिर है वो लोग इस तरह कार्यक्रमों में आ जा सकते हैं। और अगर लिबरलों के हिसाब से जवाब नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हें आपत्ति का आधार इफ्तार पार्टियों और सम्मेलनों को बनाना चाहिए जहाँ पहुँचकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग मिलते भी हैं और उनके बीच हँस-हँसकर बात भी होती है।

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:46 PM Page 4

राजनीतिक लाभ के लिए ये कैसा नेरेटिव गढ़ा जा रहा ?

नरेन्द्र पाण्डेय

दुनियाँ का सबसे खतरनाक युद्ध है नेरेटिव का जिसके लिए किसी हथियार की जरुरत नहीं पड़ती . रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद अपनी किताब the ultimate goal मे लिखते है असली सत्ता बन्दूक की नली से नहीं निकलती , असली सत्ता उसके हाथ में होती है जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है . ये महज भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए है . आज जो समूचे विश्व में जो युद्ध चल रहा है वो हथियारों का नहीं नैरेटिव का युद्ध है . अपने देश में भारत में भी 1947 के बाद से ही एक इको सिस्टम बना जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोध में खड़ा रहता है जिसे आप कई फिल्मो ,अखबारों, पात्र-पत्रिकाओं और साहित्य सामग्रियों आदि में देखते आ रहें है .फिल्म 'द कश्मीर फ़ाइल' में एक डायलोग था 'सरकार भले ही उनकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है'. वर्तमान में आपको सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो अथवा कथित गैर राजनितिक या राजनितिक आन्दोलन , इन सब को अगर समझे तो नेरेटिव बनाने का यह खेल आपको भी समझ में आने लगेगा.

गैर राजनितिक आन्दोलन से याद आया खिलाड़ियों का वो आन्दोलन जिसकी शुरुआत साल 2023 में 18 जनवरी को हुई थी , जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत 30 पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने बैठे थे , तो पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ था। उस समय इन्होंने यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी। उस समय केंद्र सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर संज्ञान लेते हुए खिलाड़ियों को मिलने बुलाकर समझाया और एक समिति का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष पाए गए हैं। पहलवानों ने इन खबरों को नकारते हुए दोबारा अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और किसी की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने समर्थकों को बताया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं जबकि उस समय तक बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जा चुका था। पहलवानों ने बताया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालाँकि देखते ही देखते इसमें खाप नेता, किसान नेता और राजनीतिक पार्टियों की शिरकत होने लगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं और खाप नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। 29 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई लेकिन पहलवान

प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने एक नया पैंतरा आजमाया। ये पैंतरा अपने मेडल हरिद्वार में प्रवाहित करने का था। हालाँकि बाद में मेडल प्रवाहित नहीं किए गए पर ये हल्ला हर जगह हुआ कि पहलवान कितने ज्यादा आहत हैं कि वो अपनी कमाई को बहाने जा रहे थे।कई राजनैतिक हस्तियों ने इस पूरे प्रदर्शन की आड़ में अपनी राजनीति खेली, बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लाकर सीधे मोदी सरकार से जोड़ दिया गया। तमाम तरह के लांछन लगाए गए, उनपर सवाल उठाए गए, मगर बावजूद इसके केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए, इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए, इन्हें सुविधाएँ मुहैया कराने पर काम करती रही। पीटी उषा खुद इनसे मिलने प्रदर्शनस्थल एक बार गईं लेकिन वहाँ पहलवानों के समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की। पीटी उषा के साथ हुई अभद्रता कोई अकेला मामला नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण कर दिया था कि 2021 के हालात देखने के बावजूद कहा गया कि दिल्ली में सारे ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। इसके अलावा जिस प्रदर्शन को पहलवान प्रदर्शनकारी गैर-राजनीतिक बताते रहे थे वहाँ 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' जैसे नारे लगाए जा रहे थे।

विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में एंट्री को लेकर लंबे समय से लग रही अटकलें 6 सितंबर 2024 को सच साबित हो गईं। दोनों पूर्व खिलाड़ियों ने आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम ही लिया है। वैसे ये दोनों कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने खेल करियर के बाद राजनीति में कदम रखा हो। पहले भी खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, अलग-अलग पार्टियाँ ज्वाइन करके राजनीति करते रहे हैं, अपना एक दूसरे से विरोध जताते रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कांग्रेस में एंट्री पर बात करना इसलिए जरूरी है . क्योंकि यौन उत्पीड़न प्रदर्शन के नाम पर 2023 से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ ये हर मीडिया में हैं और ये सवाल भी कि क्या ये सब राजनीति के लिए हो रहा है? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर उन सवालों का जवाब जरूर दे दिया है, लेकिन राजनीति में करियर शुरू करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है उसके कारण भविष्य में खेल-खिलाड़ियों की साख पर गंभीर सवाल पैदा हो सकता है। पुनिया-फोगाट के दाँव से खिलाड़ी की साख पर बट्टा लगा दिया.

राजनीति में आना या न आना खिलाड़ी की अपनी इच्छा होती है। पहले भी तमाम खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं और भविष्य में भी आएँगे। उनमें से शायद कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई मंत्री बने या संभव है कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए् लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से एक यौन शोषण के मामले को आधार बनाकर अपनी राजनीति खेली है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश की आम जनता इस तरह उठाए गए मुद्दों पर आगे विश्वास कर पाएगी। अगर कल को किसी खिलाड़ी के साथ खेल क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है और वो सामने आकर अपनी बात रखता है तो क्या कोई बिन सबूत के यकीन कर पाएगा कि ये कोई राजनीति नहीं थी, लोग तो उस खिलाड़ी जो वास्तविक में पीड़ित होगा उसे भी शक की निगाह से देखेंगे, उसमें राजनीति खोजेंगे, उस पर सवाल खड़े करेंगे।

बात मै नेरेटिव गढ़ने की कर रहा हूँ तो ओटीटी प्लेटफार्म की भी होनी चाहिए . बात उस वेब सीरीज IC814 = the kandar hijack की होनी चाहिए . जिस पर चर्चा हो रही मुस्लिमो के नाम के प्रति सॉफ्ट रवैये की . हालांकि फिल्मो का उद्देश्य तो कला के प्रदर्शन और मनोरंजन का होता है. सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मो का उद्देश्य होता है उस समय की घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा यथार्थ बनाना . लेकिन सवाल इस फिल्म को लेकर यह उठ रहा है कि उन 5 मुस्लिम हाईजैकर्स की पहचान क्यों छुपाई गई . पूरी फिल्म में केवल उनके कोड नेम का ही उपयोग किया गया . जब भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निर्माता-निर्देशक को बुलाया तो फिल्मकार ने एक डिस्क्लेमर लगा दिया जिसमे उन हाईजैकर्स के असली नाम दिखाए जायेंगे . अब आप बताइए इस डिस्क्लेमर देने से क्या फर्क पद जाएगा . कितने लोग है जो इस डिस्क्लेमर को देखेंगे . आप में से कुछ लोग कह सकते है कि नाम को लेकर जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है . एसा नहीं है .इस फिल्म के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए . इस फिल्म हमारे सेक्युरिटी एडवाइजर है जिनको आईबी का बेस्ट फील्ड ऑफिसर माना जाता है, दुनियाँ भर में उनका लोहा माना जाता है , उनको एक जोकर की तरह दिखाया गया है . यानी की भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है . इससे भी ज्यादा यह बताने की कोशिश की गई है कि इस घटना में आईएसआई का कोई हाथ नहीं है . इससे तो लगता है की यह फिल्म शायद आईएसआई को क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई है . एसा लगता है इसे पाकिस्तान के समर्थन में बनाई गई है . अब इस फिल्म के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले पर आप गौर करिए तो मेरी नैरेटिव वाली बाते आपकी समझ में आ जाएगी .

इस फिल्म के प्रति सुचना और प्रशारण मंत्रालय ने जो कदम उठाया है वो भी कमजोरी भरा लगता है . संदेश जा रहा है की हम इस नैरेटिव से लड़ने में सक्षम नहीं है . खिलाड़ियों के आन्दोलन , किसान आन्दोलन आदि के राजनितिक उपयोग को देखकर लगता है कि अगर एसा होता रहा तो आने वाले दिन बड़े चुनौतियों से भरे हो सकते है . लगातार इस बात की कोशिश होगी किस तरह झूठ का महिमा मंडन किया जाय और सत्य को शर्मिन्दा किया जाय.

जरुरत राजनितिक लाभ-नुकसान से ऊपर उठ कर कड़े फैसले लेने की. सवाल यह है कि यह जोखिम कौन उठाएगा ?

सांसदों की सीमित स्वतंत्रता

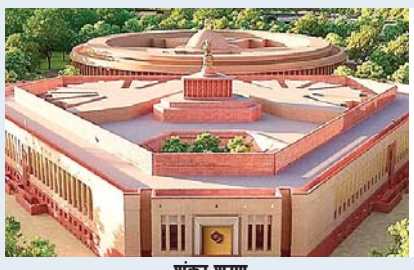

शंकर शरण

अपने देश में प्राय: ही किसी सांसद अथवा विधायक के किसी वक्तव्य पर उसकी पार्टी के नेता नाराज होकर उसकी सार्वजनिक रूप से खिंचाई करते हैं। उसे केवल पार्टी लाइन के अनुसार बोलने की चेतावनी देते हैं, जबकि जो नेता अपने दल के सांसदों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को फटकारते हैं, वे स्वयं दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए घटिया, झूठी और उत्तेजक बयानबाजियां करते रहते हैं। यह अनैतिक तो है ही, देशहित की दृष्टि से आत्मघाती चलन भी है। यदि सर्वोच्च विचार सभा यानी संसद के सदस्य ही अपने विचार नहीं रख सकते तो इसका असर अन्य सभी वैचारिक, शैक्षिक संस्थानों, क्रियाकलापों पर पड़ता है। आखिर जो अधिकार सांसद को नहीं, वह किसी अन्य को भी क्यों हो ? राजनीतिक दलों के सुप्रीमो जो तर्क अपने सांसदों का दिमाग बंद करने के लिए उचित समझ देते हैं, वह लेखक-पत्रकार, शिक्षक आदि पर लगाम लगाने में भी उपयुक्त है। सो जिस समस्या पर संसद ही विचार न करे, उस पर किसी शोध. आकलन की भी क्या जरूरत। सत्ताधारी दल अनुदान और नियुक्तियों के माध्यम से अकादमिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए कश्मीरी हिंदुओं के संहार. विस्थापन, सांप्रदायिक विद्वेष के प्रचार, संगठित मतांतरण, जिहादी आतंकवाद, तरह-तरह के आरक्षण आदि अनेक विषयों पर कोई अध्ययन-अध्यापन नहीं होता। एक तरह से संबंधित समस्याओं की पूरी अनदेखी। इस चलन का परिणाम अच्छा नहीं होगा।

संविधान का कोई अनुच्छेद, अथवा कोई नियम संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए है। राजनीतिक दलों के सुप्रीमो अपने सांसदों को इससे वंचित करके मूल मानवीय अधिकार पर चोट करते हैं। यदि सांसद की कोई बात गलत है तो उसकी गलती प्रमाणिक दिखा देना अधिक सटीक उत्तर है। इससे ही सबको लाभ होगा। जबकि सेंसरशिप से अंतत: सबकी हानि होनी है। सांसदों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से खुलेआम वंचित करना देश को दुनिया के सामने हीन भी बनाता है, क्योंकि यह अपने ही संविधान और संसद की हेठी करना है। यह नागरिकों के मूल अधिकार पर एक संविधानेतर संस्था राजनीतिक दल का अतिक्रमण है। इससे संसद का कर्तव्य बाधित होता है। आखिर सांसद जो सोच-समझ देख रहे हैं, उसे बोल ही नहीं सकते तो फिर उनकी आवश्यकता क्या है ? तब संसद का भी क्या प्रयोजन ? यह हानिकारक चलन निश्चित रूप से खत्म करना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन या अमेरिका में नियमित देखा जाता है कि गंभीरतम, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भी हरेक सांसद स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक से अपने विचार रखते हैं। उसमें उनकी पार्टी का कोई दखल नहीं है। कारण संसद सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राजनीतिक दल वहां कोई बंधन नहीं लगा सकते। सांसद पहले देश और जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। वहां उनके सोच.विचार या संसद में राष्ट्रीय नीति बनाने में पार्टी लाइन जैसी कोई बाधा नहीं है। इससे पार्टी नेता भी सतर्क और गतिशील रहते हैं। अमेरिका में एक ही दल में रहते हुए सीनेटर हर विषय पर न केवल अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक रखते हैं, बल्कि एक-दूसरे को चुनौती देते अपने लिए जनमत पाने की खुली लड़ाई भी लड़ते हैं। सांसदों को ऐसी स्वतंत्रता से ब्रिटेन, अमेरिका का लोकतंत्र अधिक मजबूत बना है। विभिन्न विचारों की खुली प्रस्तुति से ही किसी मसले की सभी बातें सामने आती हैं। तभी बेहतर समाधान पाना भी संभव है।

यह ध्यान रहे कि कम्युनिस्ट देशों में दलीय निर्देश पर सारे सांसदों द्वारा बंधी. बधाई बातें ही कहने की रीति से उनकी वैचारिक, नैतिक और राजनीतिक क्षति हुई।

अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर इस शहर की आबोहवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ, जो न सिर्फ गंगा-जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि इस धार्मिक नगरी के सामाजिक ताने-बाने पर बदनुमा दाग बन गया। उस वक्त एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में एक ऐसी खबर छपी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था।

खबर में स्कूली छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शौषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। 'बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार' शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। यह कैसे हो गया? कौन हैं? किसके साथ हुआ?

इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला कर उनसे रेप करता रहा और उन लड़कियों के घरवालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में आईएएस, आईपीएस की बेटियां भी शामिल थीं। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया था। पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई गई थी। इन लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी।

इस कांड की शुरूआत में सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया। उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली, जिनके जरिए लड़की की वह ब्लैकमेल करने लगा। उससे स्कूल की अन्य लड़कियों को बहला-फुसला कर लाने के लिए कहा। मजबूरन वो लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उन सभी के साथ रेप और ब्लैकमेल का खेल होता रहा।

एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह एक ही स्कूल की करीब सौ से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नजरों के सामने से ये लकड़ियां फार्म हाउस पर जाती थीं। उनके लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आती थीं। घर पर छोड़ कर भी जाती थीं। लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें ले ली जाती थीं। इसके बाद डरा-धमका कर और लड़कियों को बुलाया जाता। स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।

इस सेक्स स्कैंडल का मास्टर माइंड फारूक चिश्ती था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे। फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही तरह की शक्तियां थी। रेप की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थीं। रेप करने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे। इस वजह से पुलिस डरती थी।

इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसे डर था कि कहीं साम्प्रदायिक दंगे न हो जाएं और उसे संभालना मुश्किल हो जाए। धीरे-धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगी। जिसे मौका मिलता वो हाथ साफ कर लेता। लड़कियों कों ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता। यहां तक निगेटिव से फोटो को डवलप करने वाला टेक्निशियन भी इसमें शामिल हो गया था।

समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक-एक कर खुदकुशी करने लगीं। इन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता जिंदगी को खत्म करना ही समझ आया। क्योंकि, परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन तक कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। इसी बीच दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी। उनकी खबरों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।

पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए? शीर्षक से पकाशित की। खबर के साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में तूफान आ गया। तीसरी खबर सीआईडी ने पांच माह पहले ही दे दी थी सूचना, शीर्षक सेप्रकाशित हुई। चौथी खबर में प्रदेश के गृहमंत्री का बयान आया। उन्होंने डेढ़ माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र। इसके बाद क्या था, जनता ने सड़कों पर उतर कर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। सेक्स स्कैंडल को दबाने के लिए पुलिस ने खेला खेल नगर के जागरूक संगठन गुनाहकारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली। इस मामले के बारे में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत को अवगत कराया गया। उन्होंने कार्रवाई करने का वचन दिया।

मामला दबाने की कोशिश के बाद तत्कालीन उप अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा गया। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। इसके बाद इस मामले को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बकायदा प्रेस कान्फ्रेंस करके इस सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया। यहां तक कि उन्होंने चार लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए।

पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सूर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरोसिंह शेखावत ने मामला सीआईडी सीबी के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटिल अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए।

सीआईडी सीबी की एंट्री के बाद पकड़े गए आरोपी

31 मई 1992 में इस केस की जांच शुरू कर दी। इस जाच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, प्रवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जान वेसली उर्फ बबना और हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था।

आठ लोगों को दी थी उम्र कैद की सजा

इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर ली। इस मामले का पहला निर्णय छह साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने आठ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच फारूक चिश्ती पागल हो गया। जिससे उसकी सुनवाई लंबित हो गई।

कुछ समय बाद में कोर्ट ने चार आरोपियों की सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद की बजाए दस साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे डाली लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को 2012 में पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सैक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है।

आदिवासी नेता नंदकुमार साय की भाजपा में घर वापसी

रायपुर। पंद्रह महीने पहले बीजेपी छोड़कर गए सीनियर नेता नंदकुमार साय आखिरकार फिर पार्टी में वापस लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सीएम रहते साय कांग्रेस में गए थे और सात माह बाद ही कांग्रेस की सरकार जाते ही साय ने भूपेश और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि नंदकुमार साय बीजेपी में शामिल होंगे। उनके इन कयासों पर आठ महीने बाद विराम लग गया जबकि 3 सितंबर 2024 को श्री साय बीजेपी में शामिल हो गए।

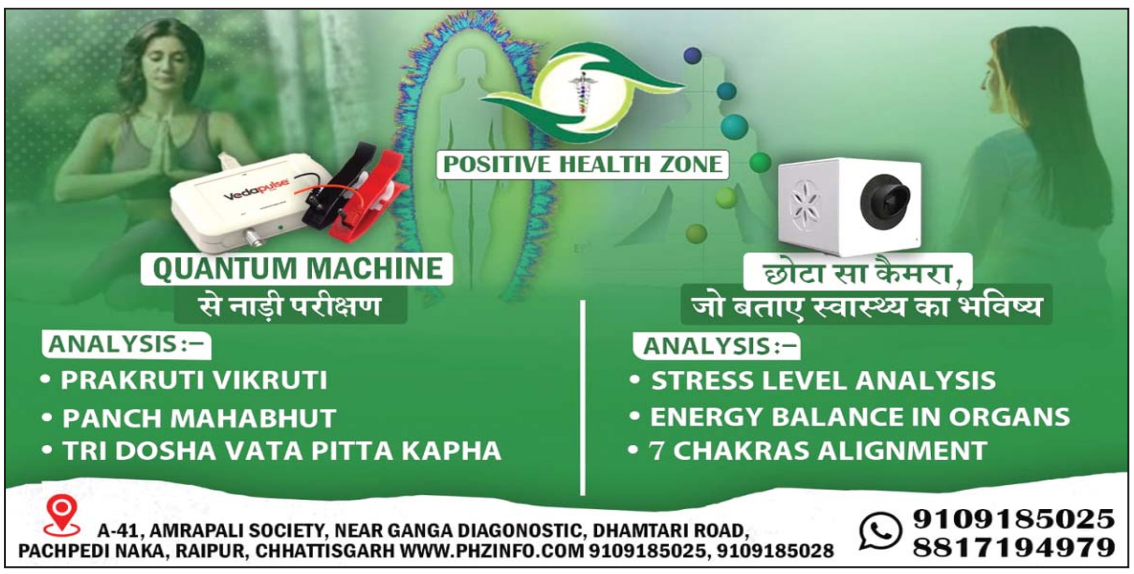

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:46 PM Page 5

संपादकीय

सर्वोच्च अदालत के भरोसे

भारत का लोकतंत्र सर्वोच्च अदालत के भरोसे है। वह ही आम आदमी को, अंततः, इंसाफ देती है। यदि सर्वोच्च अदालत न होती, तो देश का आम आदमी कराहते, चिल्लाते, इधर-उधर धक्के खाते हुए जीवन के अंत तक पहुंच सकता था! भारत में भी 'जंगल-राज' का माहौल होता! आज सर्वोच्च अदालत है, तो आम आदमी की उस तक पहुंच बेहद पेचीदा और महंगी है। ऐसे मुट्ठी भर मामले होंगे, जिनका शीर्ष अदालत स्वतः संज्ञान लेती है और फिर पीड़ित पक्ष की लड़ाई लड़ते हुए उसे न्याय देने की कोशिश करती है। लोकतंत्र की जिम्मेदारी और जवाबदेही न्यायपालिका की ही नहीं है। उसके लिए विधायिका की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन विधायक हो अथवा सांसद हो, उन्हें इस जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है। बस, उन्हें ईवीएम का बटन दबाने के लिए ही जनता की दरकार है, लिहाजा वे पांच साल के कार्यकाल के बाद, कुछ दिनों के लिए, जनता की मनुहार और गुहार करते हैं। उसके बाद जनता की मदद का संदर्भ आता है, तो वे गायब हो जाते हैं। जनता के एक-एक वोट से ही विधायक और सांसद चुने जाते हैं। हमें लगता है कि बस, जनता का दायित्व वोट तक सिमट कर रह गया है। अब औसत मतदाता, अर्थात देश का नागरिक, 'ह्यूमन वोटिंग मशीन' बनकर रह गया है। अदालतों को जनता के वोट नहीं चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों के भीतर आम आदमी, न्याय और सामाजिक-विधिक व्यवस्था अब भी जिंदा हैं। वे देश को 'केला गणतंत्र' बनने से बचाना चाहते हैं। वे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। वे अपराधियों, बलात्कारियों, व्यभिचारियों, हत्यारों और माफिया आदि को कानून के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने और दंडित करने के पक्षधर हैं। कोलकाता अस्पताल रेप-मर्डर कांड को ही लें। सर्वोच्च अदालत देश भर के डॉक्टरों की लड़ाई लड़ रही है, लिहाजा उसकी आग्रहपूर्ण अपील पर डॉक्टरों और उनके संगठनों ने हड़ताल खत्म कर दी है। अदालत का यह आग्रह मानवीय सरोकार वाला था, क्योंकि असंख्य मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहे थे। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। शायद कोई त्रासदी हुई भी हो! डॉक्टरों को भी, अंततः, मानवीय दायित्व का एहसास हुआ। इस केस का सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है।

न्यायिक पीठ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार और निर्मम हत्या की सुनवाई तो कर रही है। बंगाल की सरकार और पुलिस की नालायकी, लापरवाही, अराजकता, सांठगांठ के मद्देनजर उन्हें जवाबदेही पर टांग भी दिया है। इसके साथ-साथ अस्पतालों की चाक-चौबंद सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं। वह राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से संवाद कर अकाट्य सुरक्षा-तंत्र लागू करेंगे। कोलकाता के दागदार अस्पताल में सीआईएसएफ के जवान तैनात हो चुके हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों की 36 और 48 घंटे की निरंतर ड्यूटी को 'अमानवीय' करार दिया है। जाहिर है कि शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से यह व्यवस्था भी बदलेगी।

खाद्य कीमतों पर सतर्कता जरूरी

डा. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 22 अगस्त को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2024 में दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रगति के कारण खरीफ की बोआई अच्छी हुई है और खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में और कमी आ सकती है। इसी तरह पिछले दिनों 19 अगस्त को रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि यद्यपि देश में बेहतर मानसून, अच्छे मौद्रिक प्रबंधन और सरकार के द्वारा तत्परता से महंगाई नियंत्रण के उपायों से महंगाई घटने का सुकूनदेह परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी खाद्य कीमतों पर सतर्कता जरूरी है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि महंगाई सरकार की चिंता बनी रही है और अब सरकार ने संकेत दिया है कि महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति की डगर पर आगे बढ़ती रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा, वहीं जरूरी होने पर इन अन्य खाद्य वस्तुओं के बढ़े दामों को नियंत्रित करने के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जुलाई 2024 में घटकर तीन महीने के निचले स्तर 2.04 प्रतिशत पर आ गई। यह जून में 3.36 प्रतिशत थी। खास बात यह भी है कि 12 अगस्त को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.54 फीसदी रह गई है, जबकि जून 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.08 प्रतिशत थी। सुकूनदेह स्थिति यह है कि खुदरा महंगाई दर पिछले 5 वर्षों के सबसे कम और रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से भी नीचे आ जाने से अर्थव्यवस्था को मजूबती मिलते हुए दिखाई देगी। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि बेहतर मानसून से खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों विशेषतया आलू, प्याज और टमाटर आदि की कीमतों में बड़ी कमी आने से खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। पिछले दिनों 8 अगस्त को आरबीआई ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत रेपो रेट को पहले की तरह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह लगातार 9वीं बार है जब मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया गया है। आखिरी बार रेपो रेट में फरवरी 2023 में बदलाव किया गया था। इस मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत तेज विकास दर की बजाय महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निरंतर आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अभी भी महंगाई पर स्पष्ट तरीके से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक और सरकार के समन्वित प्रयासों से महंगाई नियंत्रण के लगातार रणनीतिक कदम जरूरी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए जो धनराशि सुनिश्चित की गई है, उससे खाद्य भंडारण से जुड़ी एजेंसियों को धन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वे उपयुक्त भंडारण बनाने के लिए किसानों के खेत या मंडी से सीधे खरीददारी कर सकें।

हम उम्मीद करें कि अगस्त 2024 में जिस तरह खुदरा उपभोक्ता महंगाई रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार फीसदी के लक्ष्य से भी कम है, उसी तरह सरकार भविष्य में भी खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित रखने के लिए प्रयास करेगी व नए दाम स्थिरीकरण कोष तथा खाद्य भंडारण व वेयरहाउसिंग के लिए किए गए बजट आवंटनों के उपयोग पर शुरुआत से ध्यान देगी

इसके अलावा नए बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी करके 50000 करोड़ रुपए सुनिश्चित की गई है। निस्संदेह नए बजट के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे अधिक खाद्यान्न उत्पाद और महंगाई नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राकृतिक खेती पर भारी प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं और आगामी दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देशभर में 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से प्राकृतिक खेती की गतिविधियां संचालित होंगी। मौसम की मार के कारण खराब होने वाली फसलों के लिए समर्थन राशि बढ़ाई जाने से कृषि को नया प्रोत्साहन मिलेगा। नए बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, दलहन-तिलहन की पैदावार बढ़ाकर और किसानों की आय बढ़ाने, बीज की समस्या के निराकरण और मुख्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने जैसे मामलों की चुनौतियों को कम करने के साथ-साथ कृषि शोध के विकास के लिए ज्यादा प्रावधान किए हैं। गौरतलब है कि 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे भी महंगाई में और कमी आएगी। पूरे देश के कोने-कोने में बेहतर मानसून के लाभ दिखाई देने लगे है। कृषि मंत्रालय ने 12 अगस्त को खरीफ फसलों का रकबा बढ़ने संबंधी रिपोर्ट में कहा है कि चालू खरीफ सीजन में अब तक खरीफ फसलों की बोआई 980 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 966 लाख हेक्टेयर ही थी। इस साल अच्छे मानसून से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी सप्लाई बढ़ने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ेगी। निश्चित रूप से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार के वित्तीय नियंत्रण और बेहतर मानसून से जिस तरह महंगाई में कमी आई है, अब इसे नियंत्रित रखने के साथ-साथ ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में इजाफा करने के लिए कुछ अहम बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा।

इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के बहुआयामी प्रयासों की कारगर रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। हम उम्मीद करें कि अगस्त 2024 में जिस तरह खुदरा उपभोक्ता महंगाई रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार फीसदी के लक्ष्य से भी कम है, उसी तरह सरकार भविष्य में भी खुदरा महंगाई दर को पूर्णतया नियंत्रित रखने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार नए दाम स्थिरीकरण कोष तथा खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए किए गए प्रभावी बजट आवंटनों के कारगर उपयोग पर शुरुआत से ध्यान देगी। साथ ही सरकार कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, खाद्य पदार्थों की बरबादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढ़ेगी।

भगवान श्रीकृष्ण सबके आदर्श

भगवान श्रीकृष्ण हमारे बहुत बड़े गुरु, आदर्श और मार्गदर्शक हैं। इन्होंने हमें बताया है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिएं। भगवान भावना के भूखे होते हैं। इनकी बाल लीलाओं को देखा जाए, इनके बारे में पढ़ा जाए, तो हमें पता चलता है कि यह अपने किसी गरीब मित्र से भी घृणा नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ हमेशा खेलते रहते थे।

जब-जब भी सृष्टि पर पाप बढ़ा है, असुरों के अत्याचार से प्राणी जाति संकट में आई है और सत्य, इनसानियत का पतन होने लगा है, तब-तब भगवान धरती पर किसी न किसी रूप में आए हैं। कभी राम बनके, तो कभी कृष्ण के रूप में। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्यार व इनसानियत से जीने का संदेश देती है। यह अहंकार छोड़ने और गलत आदतों से दूर रहने का सबक देती है।

वैदिक ज्ञान व संस्कृत भाषा की कालातीत यात्रा

संस्कृत, जिसे 'देवताओं की भाषा' के रूप में जाना जाता है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसने भारतीय सभ्यता को आकार दिया है और आधुनिक समय में भी इसकी प्रासंगिकता जारी है। यह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का गहरा भंडार है। संस्कृत वह माध्यम है जिसके माध्यम से प्राचीन वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न अन्य शास्त्रों की रचना की गई, जिससे यह सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की आधारशिला बन गई। रक्षा बंधन से तीन दिन पहले शुरू होने वाला और तीन दिन बाद समाप्त होने वाला संस्कृत सप्ताह श्रावण की पूर्णिमा के दिन के साथ मेल खाता है, जो भारतीय पारंपरिक कैलेंडर में एक शुभ अवधि को चिह्नित करता है। यह उत्सव न केवल संस्कृत भाषा संवर्धन के लिए एक शुभ अवधि है, बल्कि प्राचीन वैदिक ज्ञान के समृद्ध भंडार में तल्लीन करने का एक अवसर भी है, जो संस्कृत सप्ताह प्रदान करता है। सप्ताह अकादमिक गतिविधियों, साहित्यिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बहुत कुछ से भरा है, जिसका उद्देश्य इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। संस्कृत को अक्सर मानव सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं।

यह वह भाषा है जिसमें दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई थी। संस्कृत सिर्फ एक भाषा से अधिक है, यह एक विशाल बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा का अवतार है, जिसने भारत और उसके बाहर जीवन के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित किया है। संस्कृत भाषा को हिंदू धर्म में देवताओं की भाषा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसका उपयोग अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और समारोहों में किया जाता है, जो व्यक्तियों को परमात्मा से जोड़ते हैं। संस्कृत की संरचना इतनी सटीक है और इसकी ध्वन्यात्मकता इतनी समृद्ध है कि इसे आध्यात्मिक प्रवचन के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। वैदिक परंपरा, जो सनातन धर्म की नींव बनाती है, अपने पवित्र ज्ञान के प्रसारण के लिए संस्कृत पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वैदिक परंपरा में, 16 संस्कार (पारित होने के संस्कार) हैं, जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक मार्गदर्शन करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, जो एक बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है।

विश्व बैंक रिपोर्ट को खारिज करे भारत

डा. अश्विनी महाजन

एक अगस्त 2024 को विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। इसमें आर्थिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए विश्व बैंक द्वारा न केवल भारत बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी नकारात्मक टिप्पणी की गयी है। भारत के संदर्भ में विश्व विकास रिपोर्ट का कहना है कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के एक-चौथाई तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे। यानी एक तरह से भारत के 2047 तक विनिर्माण विकास पर सवार होकर विकसित अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। विश्व बैंक का दावा है कि यह रिपोर्ट 108 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी रहती है और जो सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत और इंडोनेशिया की औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत अधिक विकास के आधार पर तेजी से अमीर बनने के बजाय उन्हें लंबी अवधि के लिए धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मध्यम आय वाले देशों को घरेलू प्रौद्योगिकी विकास का मोह छोड़ देना चाहिए और अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों और उनकी कंपनियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयास, संसाधनों की बर्बादी होगी। इस मामले में, इस रिपोर्ट ने सरकारी सहायता देकर विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रशंसा करते हुए, ब्राजील की यह कहकर आलोचना की है कि उसने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पर कर लगाकर विदेशी प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित किया, जिसके लिए उसे परिणाम भुगतने पड़े।

भारत को आगाह किया गया है कि वह अपनी खुद की तकनीक विकसित करने की कोशिश न करे, जैसा कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने करने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति और रक्षा आत्मनिर्भरता नीति की भी आलोचना की गई है। दि इकोनॉमिस्ट लिखता है कि भारत द्वारा 509 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों की सूची से बाहर हो गया है। रिपोर्ट में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर के नाम का इस्तेमाल करते हुए लेखकों ने यह कहने की कोशिश की है कि भारत में सरकारी संरक्षण और नई (विदेशी) फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंधों के कारण, कुशल फर्म भी कुशल नहीं रह पाएंगी। रिपोर्ट कहती है कि जहां एक औसत अमेरिकी फर्म 40 साल में आकार में 7 गुना बढ़ जाती है, वहीं भारत में यह केवल दोगुनी होती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहां गलती हुई = ऐसा लगता है कि विश्व बैंक इस बात से नाराज है कि भारत सरकार ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के प्रस्ताव और शर्तों को खारिज कर दिया है और आयात शुल्क में पूरी छूट देने से इनकार कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के लेखकों को शायद यह नहीं पता कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का दुनिया में अपना एक अलग स्थान है, जिसके कारण देश में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत ऑनलाइन लेन-देन (विश्व प्रसिद्ध यूपीआई) में तेजी से विकास कर रहा है, जिसे खुद विश्व विकास रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि इसने किस तरह से व्यवसायों, खासकर छोटे व्यवसायों में क्रांति ला दी है। आज भारत का यूपीआई ऑनलाइन लेन-देन में दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और कई देश इसे अपनाने के लिए उत्सुक हैं। चूंकि भारत ने यह तकनीक विकसित कर ली है, इसलिए वह स्विफ्ट जैसी अपनी खुद की भुगतान प्रणाली बना सकता है। भारत ने मित्र देशों से रुपए में तेल खरीदने जैसे लेन-देन करना शुरू कर दिया है, जो जाहिर तौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों को पसंद नहीं है। भारत में इस तकनीक के विकसित होने के बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां बाजार से लगभग बाहर हो गई हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र एक और उदाहरण है जहां भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित कर पीएसएलवी और चंद्रयान जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज स्थिति यह है कि चंद्रयान बनाकर भारत चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। जिस लक्ष्य के लिए अमेरिका को 166 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे सिर्फ 615 करोड़ रुपए में हासिल कर लिया। जबकि विश्व बैंक को समझना होगा कि पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है और भारत रक्षा उत्पादों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत आज बड़ी तोपों, मिसाइलों, राइफलों और यहां तक कि लड़ाकू विमानों के निर्यात में भी आगे निकल रहा है। नहीं भूल सकते कि जब भारत ने इन देशों से अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक मांगी थी, तो भारत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था।

विश्व बैंक को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच रही है, जो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 फीसदी से भी अधिक है

रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर विश्व बैंक का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके साथ ही विकसित औद्योगिक देशों के रक्षा बाजार अब सिकुड़ रहे हैं और दुनिया रक्षा वस्तुओं के लिए भारत की ओर रुख कर रही है। विश्व बैंक यह क्यों भूल जाता है कि इन सभी तथाकथित 'गलतियों' के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि विकसित देश भयंकर मुद्रास्फीति और संकुचन या ठहराव की स्थिति से गुजर रहे हैं। अधिकांश यूरोपीय देश सबसे खराब मुद्रास्फीति, आर्थिक गिरावट और कर्ज के बोझ से गुजर रहे हैं और भारत भुगतान संतुलन में घाटे से बाहर आ रहा है। रुपए में पहले से बेहतर स्थिरता है, बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है, बौद्धिक संपदा में निरंतर प्रगति हो रही है और पहले की तुलना में कई गुना अधिक पेटेंट दिए जा रहे हैं, 2023 में ही भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा एक लाख पेटेंट दिए गए। 2024-25 के केंद्रीय बजट में देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। बहुआयामी गरीबी में अभूतपूर्व कमी आई है और सभी बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। गरीबों को सरकारी सहायता, बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही है।

इन सबके लिए संयुक्त राष्ट्र के यूएनडीपी जैसी संस्थाओं द्वारा भारत की प्रशंसा की जा रही है। विश्व बैंक को यह अवश्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच रही है, जो निश्चित रूप से अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 फीसदी से अधिक है। इसलिए, अगले 23 वर्षों में उच्च आय वाला देश बनने के भारत के संकल्प का मजाक उड़ाना निश्चित रूप से उचित नहीं है। कई आलोचकों का मानना है कि यदि विश्व बैंक भारत के विकास के मार्ग की आलोचना कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारत का विकास का मार्ग सही है। अतीत में भी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित देशों के इशारे पर कई शर्तें लगाकर भारत के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की गयी, और विश्व बैंक ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट के लेखकों को 'मध्यम आय जाल' के नाम पर अपने तर्कों को सही साबित करना है। उन्हें पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत की जो रणनीति अपनाई जा रही है, वह विश्व बैंक द्वारा बताए जा रहे निरर्थक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह रणनीति अतीत की सीखों और वैश्वीकरण के अंधे रास्ते से मिली सीखों का परिणाम है। भारत के नीति-निर्माताओं से अनुरोध है कि ऐसी रिपोर्टों को न केवल खारिज किया जाए, बल्कि सरकार भी विरोध दर्ज कराए।

कहां जाएं बेटियां-बहनें

प्रख्यात क्रिकेटर सौरव गांगुली को भी विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। पत्नी डोना गांगुली भी उनके साथ होंगी। उन्हें बर्बर बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार और कार्यस्थलों पर असुरक्षा सरीखे मुद्दों पर विरोध जताना पड़ा है, क्योंकि सौरव-डोना भी एक बेटी के माता-पिता हैं। इधर कुछ घटनाओं ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ कोलकाता रेप-मर्डर कांड की सुनवाई कर रही है। सर्वोच्च अदालत ने इस कांड का स्वतः संज्ञान लिया है। बंगाल सरकार और पुलिस को खूब फटकार लगाई है और उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। सरकारें बड़ी मोटी खाल की होती हैं। फटकार का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। बेशक संदर्भ कोलकाता अस्पताल में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार और बाद में हत्या का है, लेकिन शीर्ष अदालत का सरोकार राष्ट्रीय है। खासकर अस्पतालों में महिला डॉक्टर और नर्स आदि कैसे सुरक्षित रहें, इसके मद्देनजर एक टास्क फोर्स बनाने और अस्पतालों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने के महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी देशवासियों की आत्मा में लगातार गूंजती रहनी चाहिए कि बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म और हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। टास्क फोर्स को अपनी अंतरिम रपट तीन सप्ताह में देनी है और अंतिम रपट दो माह की अवधि में देनी है। फोर्स महिला सुरक्षा के उपाय सुझाएगी। गौरतलब यह है कि 'निर्भया कांड' के एक साल बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में सख्त 'पॉक्सो एक्ट' बनाया गया। उसके बाद 'पॉश' (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वूमन एट वर्कप्लेस) एक्ट बनाया गया। फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया। क्या इन कानूनों ने बलात्कारियों को डराया? हमारी व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। करीब 2.43 लाख केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इनमें पॉक्सो केस भी हैं।

हर रोज बलात्कार के केस आ रहे हैं और सरकारें फास्ट ट्रैक कोर्ट के आश्वासन देती रहती हैं।

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:46 PM Page 6

नेताओं के कामों का लेखा–जोखा जनता के समक्ष रखना चाहिए

नरेंद्र पाण्डेय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अर्थात 'जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन', जहाँ जनता अपने बीच से ही एक व्यक्ति को नेता चुनती है और वही नेता जनता के हित में काम करते हैं। वास्तव में ये नेता जनता के रिप्रेसेंटेटिव होते हैं और उनके कंधों पर जनता का विश्वास होता है। जब कोई नेता किसी पद पर आसीन होता है, तो उसके कार्य और निर्णय का असर सीधे तौर पर जनता के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में जनता को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके नेता ने क्या काम किया है, किस प्रकार के फैसले लिए हैं, और इन फैसलों का आम जनता और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है।

क्यों न ऐसा हो कि जिस तरह किसी प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों से उनके काम का हिसाब माँगा जाता है कि किसने कितना काम किया, कितनी प्रोडक्टिविटी दिखाई, और कौन कितनी छुट्टियां लेकर आराम करता रहा। और उसी के आधार पर उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी, नौकरी की निरंतरता, पदोन्नति और अन्य पहलुओं पर निर्णय लिया जाता है। उसी तरह हमारे देश के नेताओं से भी हर महीने, तिमाही, या छमाही रूप से उनके किये कामों का हिसाब भी माँगा जाए। संभवत: नेतागण अक्सर अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर जवाबदेह होते हैं लेकिन उनकी असल जवाबदेही जनता के प्रति है। दूसरा, काम का हिसाब मांगने पर नेताओं में न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि वे अधिक गंभीरता और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। साथ ही वे यह भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि उनका पद सिर्फ दो चार भाषण या सभाएं करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र, प्रदेश, देश और जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करें।

क्योंकि, ये नेता वही लोग हैं जो जनता के दिए टैक्स से अपने पद का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए यह हर नागरिक का अधिकार है कि उसे जानकारी हो कि उसकी मेहनत कि कमाई का उपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि यह नेता और जनता के बीच सीधा संबंध भी बनाएगी। साथ ही इससे जनता को पता रहेगा कि उनके द्वारा चुने गये नेता ने अपने

वादों को कितना और किस तरह निभाया है या वो वादे केवल बातें ही थे। रिपोर्ट के आधार पर नागरिक यह भी तय कर सकेंगे कि किसी नेता को अगली बार मौका देना है या नहीं।

यह रिपोर्ट अलग-अलग स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पेश की जा सकती है। जैसे छोटे स्तर पर नेता नियमित रूप से जन सभाएं आयोजित कर सकते हैं, जहाँ वे जनता के सामने अपने काम का ब्यौरा दे सकते हैं। जनता को सीधे जानकारी देने के लिए न्यूज़लेटर्स या पत्र भेजे जा सकते हैं, जिसमें नेताओं के कार्यों का विस्तृत विवरण हो। हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है, जिसमें नेता के पूरे साल के काम का सारांश हो। यह रिपोर्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी दफ्तरों, और स्थानीय समाचार पत्रों में उपलब्ध कराई जा सकती है। अभी सिर्फ चुनावों के समय ही, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत ही झूठ सच का डाटा जनता के सामने परोसा जाता है। जिसमें से आधे से अधिक कामों का कोई क्रॉस-चेक भी नहीं होता। नेताजी ने जो बोला, भोली जनता वही मान लेती है। किसे में जनता को भी ये भोलापन छोड़ना होगा।

दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने काम का ब्यौरा ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए सरकार की वेबसाइट पर एक विशेष सेक्शन दिया जा सकता है, जहाँ नेता अपने कार्यों की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। इसमें उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, खर्च की गई राशि, और भविष्य की योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियमित रूप से अपनी गतिविधियों और काम का विवरण साझा कर सकते हैं। या एक विशेष मोबाइल ऐप बनाया जा सकता है, जिसमें नेता अपने काम की जानकारी डाल सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से जनता भी सीधे सवाल पूछ सकती है और फीडबैक दे सकती है।

इस पूरी प्रक्रिया में जनता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सशक्त लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव में वोट डालना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हर नेता से सवाल करना चाहिए, और हर काम पर नजर रखनी चाहिए। हमारे सक्रिय रहने से ही नेताओं पर दबाव बना रहेगा, और मैं स्वाभाविक रूप से यह भी मानता हूँ कि काम या अधिक और अच्छे काम अक्सर दबाव में ही होते हैं। यदि रिपोर्टिंग का सिस्टम शुरू होता है तो इससे हर नेता यह कोशिश करेगा कि उसका काम सबसे बेहतर हो, ताकि जनता का विश्वास और समर्थन बना रहे। नेताओं से काम का हिसाब मांगने का विचार केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक कदम भी है, जिसे हर हाल में उठाया ही जाना चाहिए। यह कदम लोकतंत्र की नींव को तो मजबूती प्रदान करेगा ही साथ-साथ देश के विकास की गति भी तेज करने में सहायक होगा। हमारी सक्रियता ही हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी और राष्ट्र को प्रगति की ओर अग्रसर करेगी।

सजा लड़कियों को ही क्यों ?

अनामिका पाण्डेय

कोलकाता में महिला डाक्टर से रेप की वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जो कुछ भी हुआ वह वाकई में दर्दनाक था. इस घटना का असर सबसे अधिक लडकियां भुगत रही है. पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण वो मानसिक तनाव से गुजर रहीं है . एक अनजाना भय उनके सबकान्शियश माइंड में बैठ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ पित्सत्ता की मानसिकता वाले लोग अब इसका फायदा उठाने में लगे है . इस समय महिलाओं को घर में कैद करने की साजिश ने जोर पकड़ लिया है. ताकि पुरुषों के साथ कंधें से कंधा मिला कर वो चल न पाएं और वो घर में रह कर सिर्फ चूल्हा चौका संभालें. कई दशक पहले भी महिलाओं को यही कह कर डराया जाता था कि घर से बाहर जाओगी तो लूट ली जाओगी, घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है.

इस से तो अच्छी भली औरतें डरेंगी ही क्योंकि पता नहीं बहार क्या हो रहा है, जबकि सच यह है कि बहुत थोड़े से लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वह लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाएं. लेकिन इस तरह की घटनाएं होने पर हल्ला इतना मचा दिया जाता है कि बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है जगह जगह दरिन्दगे ही बसते है.

धर्म के ठेकेदारों के द्वारा इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि पारंपरिक तय भूमिका, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्ता के कारण महिलाओं के लिए घर से बाहर निकल कर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है. ये सब बाधाएं भारतीय महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी को सीमित करती है. चाहते हुए भी वे नौकरी नहीं कर पाती है या फिर पूर्णरूप से उस से जुड़ी नहीं रह पाती है.

2024 में यूनिसेफ के द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चला है कि भारतीय महिलाएं शिक्षा के तुरंत बाद शादी के बजाय नौकरी करना चाहती हैं पर उन की इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है. यूनिसेफ के यूथ प्लेटफौर्म 'युवाह' और यू रिपोर्ट के द्वारा किए गए सर्वे में देश के 18–29 साल के 24,000 से अधिक युवाओं ने अपनी राय सामने रखीं. आउटलुक में प्रकाशित खबर के मुताबिक सर्वे के परिणाम में 75 फीसदी युवा महिलाएं और पुरुषों का मानना है कि पढ़ाई

इस घटना के बाद तो पैरेंट्स भी डरे है वो अपने से दूर अपनी बेटी को अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले पा रहे. जिससे कई लड़कियों के सपने पूरे होने से पहले ही दफ़न हो रहें है .पित्सत्ता वाले समाज में कोई पुरुष यदि किसी लड़की के साथ कुछ उलटा सीधा करता है तो उसका दोष और सजा दोनों लड़की ही भुगतती है

के बाद नौकरी हासिल करना महिलाओं के लिए सबसे जरूरी कदम है. इस से अलग 5 फीसदी से भी कम उत्तरदाताओं ने पढ़ाई के तुरंत बाद शादी की वकालत की है.

इन्हीं धर्म के ठेकेदारों की साजिश का नतीजा कि लड़कियों के बाहर जौब करने व पड़नेलिखने पर पाबंदी लगा है. इस घटना के बाद तो पैरेंट्स भी डरे है वो अपने से दूर अपनी बेटी को अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले पा रहे. जिससे कई लड़कियों के सपने पूरे होने से पहले ही दफ़न हो रहें है .पित्सत्ता वाले समाज में कोई पुरुष यदि किसी लड़की के साथ कुछ उलटा सीधा करता है तो उसका दोष और सजा दोनों लड़की ही भुगतती है .

अब ऐसे माहौल को देख कर कोई लड़की किसी भी आदमी से बात करने में घबराती तो है ही, अक्सर पुरुष भी घबराता है कि अगर मैं ने लड़की की हेल्प करने की कोशिश की और इसने डर कर शोर मचा दिया तो मैं तो बेवजह ही मारा जाऊंगा. जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है ऐसे में अगर कोई लड़की कहीं जा रही हो या सड़क पर परेशान खड़ी है, तो शायद कोई पुरुष उसे लिफ्ट देने के लिए भी नहीं पूछ सकते क्योंकि हो सकता है वह इसका कुछ और ही मतलब निकाल ले ओर शोर मचा दे.

एसी घटनाओं से अब समाज में आपसी विशवास कम होता जा रहा है. लोगों का एकदूसरे पर भरोसा उठ रहा है, लोग अब दूसरों के बच्चों को शक नजर से देखते हैं. लोग सगे रिश्तेदारों के यहां अपनी लड़कियों को छोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं. अब आप ही बताइए यह कितना सही है ?

लड़कियों के साथ बुरा होने की सजा लड़कियों को ही घर में बंद कर के क्यों दिया जय . क्यों नहीं लड़कों को घर में बंद कर के भी देखा जाय. उन्हें कहा जाय कि तुम्हारे वजह से लड़कियां सुरक्षित नहीं है इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे. क्या आप ऐसा कर पायेगे. छोड़िए ये आप लोगो से नहीं होगा . आप तो बस इतना ही कर लीजिए कि बचपन से अपने बेटों को लड़कियों की इज्ज़त करना सिखाएं . लेकिन उसके लिए आप को पहले खुद अपनी बीवी की इज्जत करनी पड़ेगी. क्योंकि आप को देख कर ही तो आप का बेटा तय करेगा कि उसे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है. तो क्यों न इस के लिए शुरुआत अपने ही घर से की जाय . जब आप के अपने घर की ही नींव कमजोर है तो सजा बेटियों को क्यों ? अगर समस्या की जड़ में जाएंगे तो दीवारें अपनी ही कमजोर निकलेंगी.

महिलाओं को घर में कैद करने या उनके मन में डर बिठा देने से कोई हल नहीं होने वाला . उन्हें बाहर जाने से रोकने से भी कोई हल नहीं निकलेगा . हर माँ–बाप को अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि वह कैसी प्रवृति का है, वह हिंसक है, महिलाओं पर गंदी नजर रखता है, गलत कामों में इन्वोल्व रहता है तो बताइये क्या आप अपने बेटों के खिलाफ कुछ बड़ा घटित होने से पहले ही पुलिस कंप्लेंट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे .

हिम्मत नहीं है, तो पैदा कीजिए. और अगर यह नहीं पता कि खुद का बेटा कैसा है तो पता करें. बेटियों पर नज़र रखने के साथ साथ बेटों पर नजर रखें और उन्हें खुद सही रास्ते पर लाएं. समस्या का हल बेटियों को घर में कैद करने से नहीं बल्कि अपने ही घर के बेटों पर नजर रख कर उन्हें सुधारने से निकलेगा.

बयान, एक विचार जो बदल सकता है दिशा

हम सब दिनभर तरह-तरह की बातें करते हैं, लेकिन आम जनता के द्वारा कही गई बातों का कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन जब कोई नेता जी कुछ कहते हैं, तो वह बयान बन जाता है। नेता जी लोग दिन भर कई सारी बातें करते हैं, लेकिन सभी बातें बयान नहीं बनती हैं।

अक्सर देखा गया है कि ऐसी बात जो चुभ जाए, वह जल्द ही सुर्खियों में आती है और बयान बन जाती है। बयान/ब्यान का प्रयोग इन दो स्थानों पर बहुत होता है - एक कचहरी में और दूसरा अगर आशिकी में। अदालत में लोगों के द्वारा कहे गए शब्दों को बयान के रूप में दर्ज किया जाता है और इन्हीं बयानों से मुकदमे का मुकद्दर सुनिश्चित होता है।

फिल्मों का सुपरहिट होना उसके संवाद पर निर्भर होता है। पुरानी ऐसी कई फिल्में हैं जिनके संवाद हमारे जेहन में हैं। फिल्म में संवाद तो राजनीति में बयान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़े-बड़े नेताओं ने अपने बयानों से चुनाव परिणामों की दिशा ही बदल दी है।

बदलते समय में बयानों ने कहीं न कहीं अपना रास्ता बदल दिया है। बयान की जो गरिमा थी, अपना एक वर्चस्व था, आज की इस स्वार्थ की भीड़ में खो गई है। बयान अपने विरोधी को नीचा दिखाने के काम में लाया जा रहा है, कहीं-कहीं अपने निजी लाभ के लिए बयान को तोड़-मरोड़ कर परोसा जा रहा है।

बयान का पतन होना दर्शाता है कि उस व्यक्ति में, राजनीतिक दल में विचारों का कितना अभाव है। आज हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समस्याओं से चिंतित है, परेशान है। ऐसे में जो नेताओं के द्वारा दिए गए बयान आम जनता की मानसिक दशा को परिवर्तित करते हैं।

ऐसे में सभी दल और नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि बयान की गरिमा को बनाए रखें, उन्हें विवादास्पद बना कर हास्य का विषय न बनाया जाए। बयान के माध्यम से जन में जोश भरना चाहिए, न कि मन में आक्रोश!

डॉ. शशिकांत सिंह राजपूत,
मनोरोग विशेषज्ञ, रायपुर

बलात्कार और यौन हिंसा के डर से महिलाओं में बढ़ रही मानसिक समस्याएं

डॉ संस्कृति सिंह

बलात्कार और यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के कारण महिलाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर और यहां तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं.

पिछले कुछ समय के दौरान मनोचिकित्सकों के पास इलाज के लिए आने वाली उन महिलाओं की संख्या में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई हैउनमें रक्त चाप, हृदय रोग, अनिद्रा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने का खतरा दो से तीन गुणा बढ़ जाता है.घर या बाहर होने वाले यौन दुर्व्यवहार एवं यौन हिंसा महिलाओं में डिप्रेशन एवं एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का मुख्य जोखिम कारक है। महिलाओं को हार्मोन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

इसके अलावा उनके साथ घर एवं दफ्तर में यौन दुर्व्यवहार एवं यौन हिंसा होने का खतरा अधिक रहता है. इसके कारण आज महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को अधिक महत्व दिए जाने की जरूरत हैविश्व में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा व्यापक रूप से व्याप्त है और यह मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे भयानक रूपों में से एक है. लैंगिक असमानता, शर्मिंदगी और सज़ा के प्रति भय ना होने की वजह से अक्सर ऐसे मामलों का पता भी नहीं चल पाता है जो एक बड़ी चुनौती हैमहिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं, उनके गर्भपात कराने की संभावना दोगुनी होती है और मानसिक अवसाद का मरीज़ होने की आशंका भी बढ़ जाती है.

बच्ची या बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने का ख्याल कभी भी किसी मानसिक तौर पर फिट इंसान के मन में नहीं आता है। आम इंसान के मन में बच्ची को दुलारने और बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत का ख्याल आएगा, जबकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के मन में बच्ची और बुजुर्ग महिला को टॉर्चर करने का ख्याल आएगा।

इसे सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। इस मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को क्राइम पर बनी वेब सीरीज और फिल्में उकसाने का काम करती हैं।

क्या अपराध करने वालों को कानून का डर नहीं सताता?

कोई भी शख्स अपराधी एक दिन में नहीं बन जाता। सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग इस तरह की छोटी-मोटी गतिविधियां करते रहे हैं और उनके इस कृत्य से परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी वाकिफ होते हैं, लेकिन वे यह बात बताते नहीं हैं। यही वजह है कि बाद में चलकर ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस गिरफ्तार करती है और आरोपियों को सजा भी मिलती है, लेकिन जेल से छूटने के बाद वे फिर से क्राइम करते हैं। इसकी वजह है कि मानसिक रोगी कानून और इमोशंस के बारे में सोचने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ का भी इलाज किया जाएडिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल बिल्कुल निराशा भरी हो रही है । कई बार लोग अपने साथ हुए बुरे हादसे को भूल नहीं पाते, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई तो सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। ये प्रॉब्लम्स हर उम्र के लोगों में देखी जाती है।भारत में 15 करोड़ लोग किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और उन्हें तत्काल डॉक्टरी मदद की जरूरत है। इसमें 10 जरूरतमंद लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को डॉक्टरी मदद मिल पाती है।जब इंसान किसी वजह से डिप्रेशन या तनाव में रहता है और वह कुछ बोलने की अवस्था में नहीं होता है, वह अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है।

ऐसे में उसकी भानवाओं को आर्ट के जरिए व्यक्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इस थेरेपी में पेंटिंग, स्केचिंग, कोलाज मेकिंग, कलरिंग, मूर्ति कला आते हैं। इनके जरिए दिल की बातों को एक्सप्रेस किया जाता है। मेंटल ट्रॉमा झेल रहे लोगों और रेप विक्टिम के इलाज के लिए यह थेरेपी काफी कारगर है। इसमें वर्कशॉप के जरिए क्रिएटिव तरीके से तनाव, अनसुलझे सवलों को दूर किया जाता है और बुरी यादों को निकाला जाता है।अगर आप यौन उत्पीड़न का अनुभव करते हैं तो आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें या तुरंत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलेंबलात्कार आघात सिंड्रोम के

लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं-

चिंता, भ्रम या भटकाव, अवसाद, मुश्किल से ध्यान दे, फ्लैशबैक, मिजाज, बुरे सपने आना और सोने में कठिनाई होना , गुस्सा, निम्नीकरण, अविश्वास, डर, अपराध बोध, निराशा, अपमान, दु:ख, शर्म करो, सदमा. व्यर्थता.चिंता और अवसाद जैसे लक्षणों के इलाज के लिए दवाएं ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना आपके लिए वह देखभाल पाने का एक तरीका है जिसकी आपके शरीर और मन को ज़रूरत है और वह सहायता जिसके आप हकदार हैं। आपको दूसरों के साथ खुलकर बात करना और उन पर भरोसा करना मुश्किल लग सकता है। आपकी देखभाल करने वाली टीम आपको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी ताकि आप अपनी दैनिक चुनौतियों और अनुभवों से बिना किसी निर्णय के, अपनी पसंद की गति से निपट सकें।

बलात्कार आघात सिंड्रोम का उपचार इसे ठीक नहीं करता है। इसके बजाय, यहआपका प्रदाता आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले लक्षणों की पहचान करने, उनकी गंभीरता को पहचानने और समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग मूल्यांकन उपकरण प्रदान कर सकता है। इन मूल्यांकनों में आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में कई तरह के प्रश्न शामिल होते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रदाताओं के साथ ईमानदार और खुले रहें। आपके प्रदाता आपको जज नहीं करेंगे या आपको दोष नहीं देंगे। उनका इरादा कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। आपको ऐसा लग सकता है कि 'आगे बढ़ने' का एकमात्र तरीका इन कठिन विषयों को दूर रखना और यह दिखावा करना है कि ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन आप अपने प्रदाताओं से समर्थन के साथ सुरक्षित रूप से ठीक होने के लिए स्थान औरआपका प्रदाता आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले लक्षणों की पहचान करने, उनकी गंभीरता को पहचानने और समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग मूल्यांकन उपकरण प्रदान कर सकता है। इन मूल्यांकनों में आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में कई तरह के प्रश्न शामिल होते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रदाताओं के साथ ईमानदार और खुले रहें। आपके प्रदाता आपको जज नहीं करेंगे या आपको दोष नहीं देंगे। उनका इरादा कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। आपको ऐसा लग सकता है कि 'आगे बढ़ने' का एकमात्र तरीका इन कठिन विषयों को दूर रखना और यह दिखावा करना है कि ऐसा हुआ ही नहीं।

मैं 90 के दशक का प्रोडक्ट हूँ साहब...

मैंने एनर्जी के लिए रूहअफजा से लेकर रेड बुल तक का सफर तय किया है।

माचिस की डब्बी वाले फोन से स्मार्टफोन तक का सफर तय किया है।

मै वो समय हूँ जब तरबूज बहुत ही बड़ा और गोलाकार होता था पर अब तो अजीब सा लम्बा हो गया है।

मैंने चाचा चौधरी से लेकर सपना चौधरी तक का सफर तय किया है।

कच्चे घरों से पक्के मकानों तक का सफर...

अन्तर्देशी कागज से लेकर वाट्सएप मैसेज तक का...किया है।

टांके लगी निक्कर से जींस तक का सफर...किया है।

मैंने बालों में सरसों के तेल से लेकर जैल तक का सफर तय किया है।

चूल्हे की रोटी में लगी राख़ का भी स्वाद लिया है तो पिज़ा ओर बर्गर भी।

मैंने दूरदर्शन से लेकर 500 निजी चैनल तक का सफर तय किया है।

मैंने खट्टे मीठे बेरों से लेकर कीवी तक का सफर तय किया है।

संतरे की गोली से किंडर जोय तक का सफर तय किया है।

आज की पीढ़ी का दम तोड़ता हुआ बचपन में देख रहा हूं लेकिन आज की पीढ़ी मेरे समय के बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकती।

मैंने ब्लैक एंड व्हाइट समय में भी रंगीन बचपन जिया है।

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:46 PM Page 7

पुरानी शैली बदलें, पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण करें - साय

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश– पूरी पारदर्शिता से अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाए और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका यथासंभव शीघ्र निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की भाषा-शैली मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को जनसामान्य से संयमित लहजे में बातचीत करने की हिदायत दी और कहा कि यदि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखें, तो उन पर तत्काल सख्त कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। इस बात का ध्यान जिला

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई

प्रशासन को रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के किए जाने से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य की भूमि संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों एवं समस्याओं का निदान पूरी संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने जिलेवार कलेक्टरों से अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे जिले जिनकी प्रगति 70 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नरों को अधीनस्थ जिलों का नियमित दौरा कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान

स्कूली छात्राओं को समय पर साइकिल वितरित करने को कहा, इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसके साथ ही हमने चिन्हांकित किये गये लगभग 47 हजार आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय भी लिया है। इस पर भी जुट कर काम करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वच्छता सर्वे अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव और ग्राम पंचायतें स्वच्छता सर्वे को सभी मानदंडों को पूरा करती हों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत हैं। मनरेगा रोजगार सृजन का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी अधोसंरचनाएं तैयार करें। मनरेगा में भुगतान संबंधी दिक्कतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के साथ ही ट्रेनिंग, बैंक लिंकेज आदि की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पंचायतों का व्यापक निरीक्षण करने, वहां की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का तेजी से निर्माण कराए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने और आवश्यकतानुसार दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर सेवाएं लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का सभी जिलों में संचालन तथा रोगियों को लाभ सुनिश्चित करने, आगामी 6 माह में शत प्रतिशत आयुष्मान पंजीयन करने, पीएम जनऔषधि केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर जिले में बेहतर स्थिति की सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों को भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरस्वती सायकल योजना के वितरण में कुछ जिलों में हुई लेट-लतीफी को लेकर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सायकल का वितरण शिक्षा सत्र शुरू होते ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुकमा एवं बलरामपुर जिले में साइकिल वितरण अब तक न होने पर की स्थिति को देखते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले में वन अधिकार पट्टा के कार्य में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और जिन जिलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 80 प्रतिशत से कम है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा और कलेक्टरों को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही, छात्रावासों में भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए महतारी वंदन योजना को सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई पात्र महिला वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कुपोषण को जड़ से समाप्त करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री पी. दयानंद तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।

निर्माण कार्यों के साथ सांस्कृतिक विकास भी जरुरी - वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 10 करोड़ 34 हजार रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इसमें नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में 7 करोड़ 3 लाख 98 हजार रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं 2 करोड़ 96 लाख 36 हजार रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत 50 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल की मांग पर लगभग एक करोड़ 26 लाख रूपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि नगरपालिका को सुंदर, स्वच्छ बनाने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आपसी भाई-चारा के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी।

पुलिस में 341 विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने दी मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा 341 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमाण्डर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) शामिल हैं।

इन रिक्तियों से छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। साथ ही, युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी।

प्रदेश में सरकारी डाक्टरों के वेतन 46 प्रतिशत तक बढ़े

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।

प्राध्यापक को अब अनुसूचित क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा 1 लाख 90 हजार रूपए वेतन

जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गयी है। इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का ये आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है।

ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रमों का हो सफल आयोजन– मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व के आयोजन के सम्बंध में की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यहां अपने निवास कार्यालय 75 दिन तक मनाये जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें

तिथिवार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिसमें बताया गया कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुड़िया दरबार का आयोजन होगा।

इसी तरह बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए बस्तर मड़ई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम, बस्तर टूरिस्ट सर्किट, दसरा पसरा, नगरगुड़ी टेंट सिटी, टूरिज्म ट्रेवलर्स आपरेटर मीट, देव सराय, स्वच्छता पखवाड़ा जैसे विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष यात्री बसों के संचालन के सम्बंध में भी चर्चा की गई।

4 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से शुरू हुए ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व 2024 के अंतर्गत 2 अक्टूबर को काछनगादी पूजा विधान, रेलामाता पूजा विधान। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा विधान, रथ परिक्रमा पूजा विधान। 12 अक्टूबर को मावली परघाव विधान, 15 अक्टूबर को काछन जात्रा पूजा विधान और मुरिया दरबार, 16 अक्टूबर को कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान, 19 अक्टूबर को मावली माता जी की डोली की विदाई पूजा विधान आयोजित है।

मुरिया दरबार

गौरतलब है कि मुरिया दरबार में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रमुख, नेता और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं को सहेजने और सामुदायिक मांग तथा समस्याओं पर विचार करते हैं।

इस वर्ष 15 अक्टूबर 2024 को मुरिया दरबार का आयोजन किया जायेगा। मुरिया दरबार आयोजन के 10 दिन बाद बस्तर संभाग के मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, पुजारी, कोटवार, पटेल, मातागुड़ी के मुख्य पुजारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कई अभिनव पहल की जा रही है। द बस्तर मड़ई के अंतर्गत बस्तर की प्राकृतिक सौन्दर्य, एतिहासिक एवं पुरातत्विक स्थलों, एडवेंचर स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा द बस्तर मड़ई की अवधारणा तैयार की गयी है।

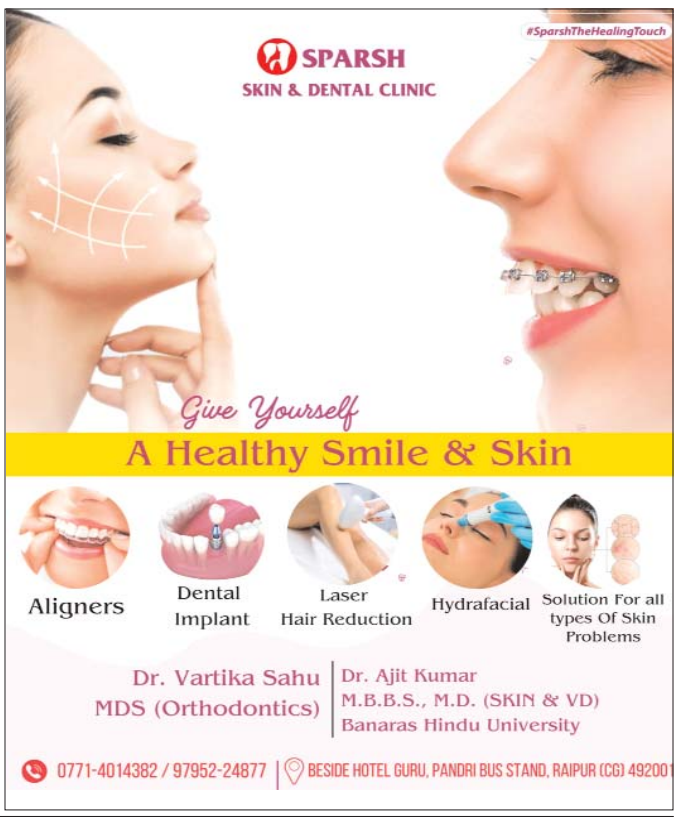

Lifevarsity Sep.24-2.qxd 9/14/2024 1:47 PM Page 8

क्या आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं

डॉ स्मृति सिंह

क्या आपको लगता है कि आप अपने आस-पास के लोगों के लिए जितना करते हैं, वो आपको उसके बदले उतना प्यार नहीं देते –

टेकन फॉर ग्रांटेड का अर्थ है किसी वस्तु या इन्सान को कम आंकना और यह मान लेना कि वह हमारे पास हमेशा रहेगा।

उदाहरण –

कई बार हम अपने स्वास्थ्य को "for granted" ले लेते हैं, और ध्यान नहीं रखते।

क्या हम लोगों को हल्के में लेते हैं?

मेरा मानना है कि हम ऐसा करते हैं। इसकी शुरुआत परिवार से होती है और फिर समाज और संगठनों तक भी इसका विस्तार होता है।

चलिए हम परिवार से शुरुआत करते हैं।

क्या हम अपने माता-पिता को हल्के में लेते हैं?- हां, हम ऐसा करते हैं। हम लगभग यह मान लेते हैं कि वे हमारे जीवन भर हमारी और हमारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बाध्य हैं। हम उनके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन अगर वे हमारी जरूरत के समय हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम खुद को ठगा हुऐसा क्यों है कि

यदि आप टेकन फार ग्रांटेड नहीं होना चाहते हैं तो आप अपने रिश्तों में कुछ सीमाएं पहले से ही निर्धारित करें कि आप ऐसी बातें नहीं सहने वाले हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप इस बात को सहन नहीं करेंगे। आप अपने लिए आवाज उठाएं, लोगों को अपना फायदा उठाने न दें।

बिना मांगे किसी की मदद न करें

आप बिना मांगे किसी की मदद न करें क्योंकि बिना मांगे मदद करने से व्यक्ति को उस मदद का अहसास नहीं होता है। इसलिए जब तब किसी को आपकी जरूरत न हो आप उसकी मदद न करें। हर किसी के लिए तत्पर रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपका खुद से पहले दूसरों को आगे रखने का स्वाभाव आपसे नए अवसरों को छीन सकता है।

हर किसी से अपनी बातें शेअर न करें

आप हर किसी से अपने दिल की बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा व्यक्ति आपकी बातों के जरिये आपकी कमजोरी का पता लग सकता है। इसलिए अपनी निजी बातों को हर किसी के साथ शेयर न करें।

हम जीवन में हर किसी को हल्के में लेते हैं? मेरा मानना है कि यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है। मनुष्य यह मानता है कि पूरी दुनिया उसका साथ देने के लिए मौजूद है। हम मानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, काम पर सहकर्मी और समुदाय के लोग हमें जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए बाध्य हैं। जब यह विश्वास एकतरफा हो जाता है, तो हम लोगों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं।लोग उन चीजों को महत्व देते हैं और उनकी सराहना करते हैं जो दुर्लभ हैं या जिनके लिए उन्हें काम करना पड़ता है । इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास किसी चीज तक लगातार पहुंच होती है, तो हम उसे महत्व नहीं देते हैं और इसे हल्के में लेने की अधिक संभावना होती है।किसी चीज़ के बारे में कभी न सोचना क्योंकि आपको लगता है कि यह हमेशा उपलब्ध रहेगी या बिल्कुल वैसी ही रहेगीअब जो लोग आपसे जुड़ें हैं, वो केवल आपसे अपना काम निकलवाते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ऐसे में आपको खुद में कुछ बदलाव लाने की ज़रुरत हैयदि आप टेकन फार ग्रांटेड नहीं होना चाहते हैं, तो आप अपने रिश्तों में कुछ सीमाएं पहले से ही निर्धारित करें कि आप ऐसी बातें नहीं सहने वाले हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप इस बात को सहन नहीं करेंगे। आप अपने लिए आवाज उठाएं, लोगों को अपना फायदा उठाने न दें।

बिना मांगे किसी की मदद न करें

आप बिना मांगे किसी की मदद न करें क्योंकि बिना मांगे मदद करने से व्यक्ति को उस मदद का अहसास नहीं होता है। इसलिए जब तब किसी को आपकी जरूरत न हो आप उसकी मदद न करें। हर किसी के लिए तत्पर रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपका खुद से पहले दूसरों को आगे रखने का स्वाभाव आपसे नए अवसरों को छीन सकता है।

खुद की इज्जत करना सीखें, तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे।किसी के लिए हमेशा तत्पर न रहें। इससे दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में आपका महत्व कम होता है। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उसे लगता है कि ये काम आपका है और आपके पास कोई अन्य काम करने को नहीं है। ऐसे रिश्ते में व्यक्ति आप पर कुछ चीजों को लेकर हावी होने लगता है। इसलिए आप किसी का डोर मैट बनने से बचें और खुद का फायदा लोगों को न लेने दें।आप खुद में आत्मविश्वास जगाएं और खुद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में अभिव्यक्त करें। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर किसी से अपनी दिल की बात करें। आप खुद में आत्मविश्वास जगाने के लिए लोगों से बातचीत करें लेकिन सभी से भावनात्मक रूप से न जुड़ें। इससे लोग आपका फायदा नहीं उठा पाएंगें।

महाभारत के कुछ प्रसंग जिनके निहितार्थ बड़े काम के हैं

1. सामना जब अपने प्रतिद्वंदी से हो तब आपकी तैयारी कितनी है यह ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है । जब युधिष्ठिर और दुर्योधन में द्यूत क्रीड़ा अर्थात पासे का खेल खेला गया तब दुर्योधन ने अपनी ओर से उसके माहिर खलाड़ी मामा शकुनि को लगा दिया । पांडवो को लगा कि इस खेल में हम ही काफी हैं सो उन्होंने यहीं चूक कर दी ,उन्होंने अपने चतुर सखा कृष्ण को भुला दिया और ये उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी । माहिर खलाड़ी से माहिर खिलाड़ी को भिड़ा देते तो पांडवो की ऐसी दुर्गति नही होती अर्थात यदि उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर से खेलने के लिए नियुक्त कर दिया होता तो हार होती ही नही ,,,,कहने का मतलब ये की तैयारी में जरा सी चूक बड़ी हार का कारण बन जाती है । जो भी कोशिश हो ,तैयारियां हों वह 100 फीसदी तक हो साथ ही अपने सामर्थ का आकलन होना चाहिए ,,,
2. भीष्म जब बाणों की शैया पर सोए थे भीषण कष्ट में उनके प्राण अटके थे तब अर्जुन नित दिन उनकी सेवा में हाजिर होते कुछ ज्ञान लाभ लेते एक दिन वे श्री कृष्ण के साथ पितामह से मिलने आये । बातो ही बातो में (भीष्म पितामह के मन मे कहीं न कहीं अपनी इच्छामृत्यु का अभिमान शेष था) उन्होंने अर्जुन से कहा कि....अर्जुन तुममे कहाँ इतनी सामर्थ थी कि तुम मुझे मार पाते मेरी इच्छा हुई इसलिए तुम्हारे तीर मुझे लगे ,,,इस पर भगवान ने कहा कि पितामह वो इच्छा कहाँ से आई ?

और तब पितामह को अहसास हुआ कि वो इच्छा भी उनके कारण ही जन्मी कहने का भाव यह कि हम केवल निमित्त बनते हैं हमे नचाने वाले वे ही हैं । जब तक वे नाटक में हमे पात्र बनाते हैं हम बनते है जब हमारा पात्र नही रह जाता तब वे हम पर पर्दा गिरा देते हैं इसलिए किस बात का अभिमान,,, ?

.....रुकता नही तमाशा रहता है खेल जारी,,,
उस पर कमाल देखो दिखता नही मदारी.....

3. हालात उनकी कृपा से अनुकूल होते हैं ,,,,

अर्जुन जब द्रौपदी स्वंयवर के समय जल में मछली के प्रतिबिंब से मछली की आंख पर निशाना लगाने जाते हैं तब उनके मित्र कृष्ण अनेक तरह से उन्हें समझाते हैं उनकी बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि यदि सब मैं कर लिया तो फिर आपकी जरूरत क्या है ?

तब भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे वश में नही है उन्हें मैं वश में करूंगा अर्थात हिलते डुलते जल को मैं स्थिर करूंगा । कहने का भाव यह कि सब कुछ आपके हाथ मे नही होता आप केवल बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकते हैं, उन्हें मुकाम तक पहुंचाना ईश्वर के हाथों में है ।

जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेने के बाद सूर्यास्त के पहले अर्जुन उसे मार नही पा रहे थे क्योंकि वह बाहर ही नही आ रहा था तब सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर उसे बाहर आने के लिए विवश करने का काम भगवान ने किया ।

अस्तु, इन कथा प्रसंगों से जीवन को एक दृष्टि मिलती है हमारी राहें स्पष्ट होती हैं ,,हम ज्यादा सटीक होते जाते हैं ,,,सटीक निशाना ही लक्ष्य भेदन कर सकता है,,,।

महिला सुरक्षा हो पहली प्राथमिकता

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अगर कोई लड़का नाबालिग लड़की से प्यार का इजहार करने के लिए लगातार उसका पीछा करता है, तो यह पॉक्सो कानून के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर होगा। दरअसल अमरावती की एक अदालत ने 4 फरवरी 2021 को एक युवक को नाबालिग लड़की का पीछा करने पर दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अपीलकर्ता ने दावा किया था कि उसे झूठे केस में फसाया गया है, क्योंकि पीड़िता किसी और लड़के के साथ संबंध में थी। लेकिन हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में इस अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सानप ने तथ्यों के मद्देनजर कहा कि पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की उस पर कोई रुचि नहीं थी। बावजूद इसके अपीलकर्ता बार-बार उसका पीछा कर रहा था। वह उससे बात कर प्रेम संबंध बनाना चाहता था। वह इस उम्मीद में बार-बार उसका पीछा कर रहा था कि एक दिन वह उसके प्रेम को स्वीकार कर लेगी, जबकि पीड़िता की अपीलकर्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

करीब साढ़े तीन दशक पहले फिल्म आई थी डर, जिसका बहुचर्चित गीत है 'तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण।' इस गीत में मधुरता के अलावा सब कुछ बेहद डरावना है, क्योंकि लड़की की मर्जी को यहां पुरुष के अहम तले कुचला जा रहा है। और लड़की जब नाबालिग हो तो यह मामला और संगीन हो जाता है। इस वक्त जब देश में यौन उत्पीड़न और महिला सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस खड़ी हो चुकी है, उसमें नागपुर बेंच का यह फैसला काफी मायने रखता है। अमरावती की जिस घटना पर आरोपी को सजा सुनाई गई, वैसी घटनाएं इस देश में हर रोज़ हज़ारों बार घटती हैं। लाखों लड़कियां छेड़खानी को किसी भयावह श्राप की तरह सहती हैं और अक्सर इस पर शिकायत नहीं करती, क्योंकि इसमें भी या तो उन्हीं की गलती तलाशी जाती है या फिर उनके पढ़ाई और करियर पर रोक लगा दी जाती है। बहुत से मामले तो ऐसे भी हुए हैं, जब लड़की की शिकायत पर परिजन उसका साथ देने आगे आएं, तो उनके साथ हिंसक व्यवहार होता है। छेड़खानी या यौन शोषण के मामले में लड़की अगर निचली जाति की हुई तब उसके लिए कानून के दरवाजे पर पहुंचना और कठिन हो जाता है।

छेड़खानी के मामलों को नजरंदाज करना या उन पर किसी कड़ी सजा का प्रावधान न होना ही आगे जाकर बड़ी घटनाओं का रास्ता खोलता है। देश इस वक्त ऐसे कई मामलों पर फिर से समाज को उद्वेलित होता देख रहा है। कोलकाता मामले में तो अब सुप्रीम कोर्ट ही स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। जिसमें सभी संबंधित पक्षों से कई तरह के सवाल हो रहे हैं। डॉक्टरों के सामने अपनी सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने कहा है, साथ ही एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, जो डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों, सहायकों, नर्सों समेत सभी हितधारकों की बात सुनेगा। कोलकाता मामले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है। खुद मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ ने कहा कि वे एक परिजन की बीमारी के दौरान सरकारी अस्पताल की फर्श पर सोए हैं और उन्होंने देखा है कि डॉक्टरों को 36-36 घंटे काम करना पड़ता है। जूनियर डॉक्टरों का हर तरह से शोषण होता है, यह बात भी शीर्ष अदालत के संज्ञान में आई है।

कोलकाता मामले में पीड़िता के परिजनों को ये इंतजार है कि इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर फिर से सियासत तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में भाजपा प. बंगाल की तरह आवाज ऊंची नहीं कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में उसी की सत्ता है और जिस स्कूल में यह वारदात हुई, वह भाजपा से जुड़ा व्यक्ति है। इस मामले में प्राथमिकी भी तभी दर्ज हो पाई, जब जनता इस पर नाराज होकर सड़कों पर उतरी। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता।

'रिश्ते' और 'रास्ते'

'रिश्ते' और 'रास्ते' के बीच,
एक अजीब रिश्ता होता है।
कभी 'रिश्तों' से 'रास्ते' मिल जाते है,
और कभी
'रास्तों' में 'रिश्ते' बन जाते हैं!
इसीलिए चलते रहिये और रिश्ते निभाते रहिये
खुशियाँ तो चन्दन की तरह होती हैं,
दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी अंगलियाँ भी महक जाती हैं

शिक्षक दिवस

शिक्षक के प्रति
सवाल उठ रहा
पिता तुल्य शिक्षक
भक्षक कैसे बन गया

कौन करेगा विश्वास
शिक्षा केंद्रों पर
जो शिक्षा का भक्षण कर
मर्यादा का हरण कर रहा

सजा गवाहों में
अटक भटक रही
कुकर्मियों की
निडरता बढ़ रही

सजा का कोई औचित्य
नहीं रह गया
जीने का मूल्य बढ़ गया
सजा का खौफ खत्म हो गया

तारीख पे तारीख
जमानत फीर से जमानत
समाचार यात्रा के लिए
तैयार हो गया

सम्माननीय शिक्षक
निःशब्द हो गए
शिक्षक विद्यार्थी
सुरक्षित शीक्षा
का समुद्र मंथन
करने लगे ...

प्रमिला शर्मा
खरियार रोड (ओड़ीसा)

भावभीनी श्रद्धांजलि

हां मैं मौमिता .....
चल पड़ी थी अपनों के साथ
सपनों को साकार करने
सभी के जैसे मैंने भी
अपने सपने जो बुने थे

सपनों की मंजिल की ओर
कंटीले कंटक को सहते हुए
निर्भय हो पथ की पथीक बन
आगे बढ़ रही थी

उस अज्ञात पथ
की मृगतृष्णा ने
मुझको दरीदंगी के
आवेश में फांस लिया

निर्भया की स्मृतियां
मुझे झकझोर रही थी
लेकिन दरिंदों के आगे
मेरी शक्ति तार तार हो रही थी

न्याय की देवी से
मैं क्या न्याय मांगू
जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है
और सबूत जुटा रही है

दरिंदों के अंग भंग कर
जनता के हवाले कर ना
यही सजा की मांग
की आवाज उठनी चाहिए

कब आंखें खुलेगी
कब न्याय मिलेगा
तब तक न जाने कब तक
यह सिलसिला चलता रहेगा
चलता रहेगा.....

प्रमिला शर्मा
खरियार रोड (ओड़ीसा)

चंद लाइने

शाम तक सुबह की लपटों में हम उतर जाते है
इतने समझौते पर जीते है कि
दिन में रात की तरह गुजर जाते है.

इस बारिश की चाहते भी अजीब है
किसी ने नहीं चाहा तब भी हमारे करीब है
वरना कौन आसमां से नीचे उतरता है
जमीं पर आ के ये कैसा रिश्ता निभाता है
अब तो खेतों ने विदाई के लिए पुकारा है
लौट जाओ बारिश ले लो हमसे चुकारा .

विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले
आसमान में उड़ानों से तय होगा सितारों की तकदीर ..
नज़ारे आसमान में है
परिन्दे अभी उड़ान में है
लगता है जिन्दगी इम्तिहान में है
खौफ अजीब सा हर इंसान में है.

मंजर धुंधला हो सकता है मगर मंजिल नहीं
दौर बुरा हो सकता है मगर जिन्दगी नहीं .

इबादत वो है जिसमे जरूरतों का जिक्र न हो
हो तो बस एक कि, उनके रहमतो का शुल्क न हो

ख्वाहिशो को जेब में रखकर निकला करो जनाब
बहुत खर्चे है ख्वाबो के मंजिल मिलने में .

कोई खुशियों की चाह में रोया
तो कोई दुखों की बात में रोया
अजीब सिलसिला है ये जिन्दगी का
कोई भरोसे के लिए रोया
तो कोई भरोसा करके रोया.

चंद्रशेखर साहू

उद्वेग

थक चुकी तन मनसे
फीर भी हिम्मत जुटा
घर का मुखौटा लगाकर
घर को संजो रही थी
शक्ति विहिन हो
टूट चुकी थी रीढ की हड्डी
फिर भी खोखले भावोंकी
संरचना को झेल रही थी

विश्वास था कि स्नेह के रोगान से
दिपावली चमक जाएगी
लेकिन ,रौद्र रूप लिए पवन ने
दीए की रोशनी
तमस को भेंट कर दी थी

मन के अनगिनत प्रश्न
अब थक चुके थे
जीवन भी अब थम सा गया
पर सांसें काम कर रही थी
क्यों इतना अंतरद्वंद
सर्वस्व की तिलांजलि देकर भी..
अनर्थ के ठट्ठेग को शांत
नहीं कर पाई .....

थक चुका अब तन और मन
खुद की खुशी का समय
समय के समय से
बहुत आगे बढ़ गया था

प्रमिला शर्मा
खरियार रोड
ओड़ीसा

प्रेरक

स्वामी विवेकानन्द जी कहते थे कि ममता तो ज्ञान की तलवार से ही काटी जा सकती है

और उसके लिए जरुरी है अतीत के मोह से छुटकारा । अतीत का प्रेम ममता का कारण होता है ।

अर्जुन को युद्ध के मैदान में मोह हो रहा है

वे अतीत से मुक्त नहीं हो पा रहे है ।

वही ताऊ ,वही गुरु ,वही तात ,वही सखा ,वही भाई मामा भतीजा बहुत मुश्किल में फंस गए है ....

बहुत पीड़ा हो रही है..... अपनों से लड़ूंगा अपनों को मारूंगा ?

श्री कृष्ण उनकी ममता और मोह को ज्ञानतत्व की तलवार से काटते है ।

और ऐसा करना ही उचित है , जिनके मोह ममता में पड़े हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है । खुद हताश निराश जीवन का रस खतम कर रहे हो।

सन्यास के बाद स्वामी जी को भी एक बार माँ और भाई की चिंता हुई थी तब ठाकुर ने उनकी ममता को अपने प्रभाव से खत्म किया था ।

लघु- व्यंग्य

फेस बुक

क्लास के दौरान एक लड़के ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखा,-'मैं क्लास में फेसबुक प्रयोग कर रहा हूं।'

प्रोफेसर ने फौरन कमेंट किया,- 'क्लास से निकल जाओ।'

प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को 'लाइक' किया। दोस्त ने कमेंट किया,-'ओए, कैफे आ जा।'

मां ने कमेंट किया,- 'नालायक कही का, क्लास नहीं अटैंड करनी तो सब्जी लेकर घर आ ।'

पापा ने फौरन कमेंट किया- 'देख लो अपने बेटे की हरकतें।'

उसी वक्त गर्लफ्रेंड का कमेंट आया,- 'धोखेबाज, तूने तो कहा था कि हॉस्पिटल में हूं। दादी आखिरी स्टेज पर हैं इसलिए मिलने नहीं आ सकता।'

और आखिर में खतरनाक कमेंट। दादी ने कमेंट किया,- 'तेरे मुंह में कीड़े पड़ें, नालायक। मैं अभी जिन्दा हूं।'